

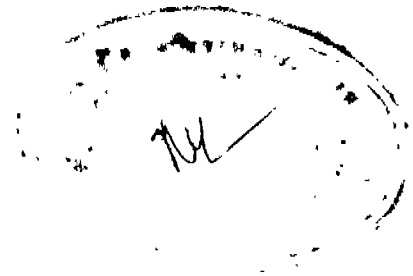


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 43] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1995/फाल्गुन 25, 1916
No. 43] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1995/PHALGUNA 25, 1916

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बजट अनुभाग)
अधिमूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1995

फा.सं. 15(38)-बी(डी)/94 :—निम्नलिखित को
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता
है :—

बजट 1995-96
वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का भाषण
15 मार्च, 1995
भाग-“क”

महोदय,

मैं वर्ष 1995-96 का बजट प्रस्तुत करने के लिए
उपस्थित हूँ।

2. चार वर्ष पूर्व श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व
में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के समय

कार्यभार संभाला था। हमारा तात्कालिक कार्य राष्ट्र को
गिरने हुए उत्पादन, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति तथा अत्यधिक
गरीबी के अग्रगम्य गर्त में लगातार गिरने से बचाना था।
हमने इस तात्कालिक संकट का तेजी से मुकाबला
किया और साथ ही हमने अर्थव्यवस्था को तेज और रोजगार-
सृजनकारी वृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के व्यापक
उद्देश्य से भी कार्य किया। हमारा लक्ष्य भारत को अंत-
राष्ट्रीय समुदाय में उसका उचित स्थान दिलाना था।

3. कभी-कभी राजनीतिक वाद-विवाद की गर्मागर्मी
में हम उपलब्धियों को नजरअन्दाज कर देते हैं। यहां
मैं यह बताने के लिए चन्द मिनट का समय लूंगा कि
1991 के उस त्रासद समय से हम कितना आगे निकल आए
हैं :

* 1991-92 में हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि
दर घट कर एक प्रतिशत से भी कम रह
गई थी। उसके बाद के दो वर्षों में हम अर्थ-
व्यवस्था को प्रति वर्ष 4.3 प्रतिशत की वृद्धि
दर पर वापस लाए और यह दर 1994-95
में 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गई है। कुछ ही
वर्षों में गहन आर्थिक संकट से इतनी

जल्दी तथा सरलता से उबरने का दावा कर सकते हैं।

- * औद्योगिक वृद्धि 1991-92 में लगभग एक प्रतिशत के आधे प्रतिशत तक गिर चुकी थी। आज भारतीय उद्योग उत्साहवर्धक एवं व्यापक सुधार का अनुभव कर रहा है जबकि अप्रैल-नवम्बर, 1994 में औद्योगिक वृद्धि 8.7 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण क्षेत्र में और भी तेजी से 9.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है तथा पूंजीगत माल क्षेत्र में 24.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मुझे आशा है कि जिन आलोचकों ने यह भविष्यवाणी की थी कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक सुधारों से भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचेगा, वे इस वास्तविकता को देखेंगे तथा अपने कहे पर फिर विचार करेंगे।
- * जैसे-जैसे भारतीय उद्योग ने आधुनिकीकरण करके प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है और इसका प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है, वैसे-वैसे 1994-95 में देशीय औद्योगिक निवेश में टोम पुनरुद्धार के लक्षण दिखाई दिए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का रुख भी नई नीतियों के काफी अनुकूल रहा है जिससे प्रमुख आधारभूत संरचनात्मक क्षेत्रों जैसे बिजुत तथा दूर-संचार में बड़ी मात्रा में निवेशों का आगमन हुआ है।
- * 1991-92 में खाद्यान्न उत्पादन गिरकर 168 मिलियन टन हो गया था। इस वर्ष यह 185 मिलियन टन होगा जो अब तक का अधिकतम रिकार्ड होगा। हमारे किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने वाली नीति से स्पष्ट तौर पर लाभ पहुंचा है और उनका उत्पादन संबंधी कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा है।
- * खाद्यान्न के सरकारी स्टॉक, जो खराब मौसम और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अमूल्य बीमा प्रदान करना है, तीन वर्ष पहले गिरकर 14.7 मिलियन टन हो गया था। इसे 1 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार 31 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पुनःस्थापित किया जा चुका है।
- * अर्थव्यवस्था में वृद्धि से हमारी जनता के लिए नई नौकरियां सृजित हुई हैं। 1991-92 में कुल रोजगार में केवल लगभग 3 मिलियन तक की ही वृद्धि हुई थी। उसके बाद प्रत्येक दो वर्षों में रोजगार में बड़ी तेजी से दुगुनी वृद्धि हुई जिससे प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन नई नौकरियां बड़ी हैं। यह वृद्धि

1994-95 में और भी अधिक होने की आशा है। सुधारों के परिणामस्वरूप व्यापक बेरोजगारी की भविष्यवाणी करने वाले भ्रमंगल-वक्ता निश्चित रूप से गलत सिद्ध हुए हैं।

- * 1991 में हमारी विफलता का तात्कालिक कारण विदेशी भुगतानों का मुचारू रूप से व्यवस्थित कर पाने में असमर्थ रहना था। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस उल्लेखनीय परिवर्तन में अवगत होंगे जो कि इस क्षेत्र में घटित हुआ है। निर्यातों का डालर मूल्य 1991-92 में 1.5 प्रतिशत कम हो गया था। 1994-95 के प्रथम 10 महीनों में हमारे निर्यात में 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। इसके पहले 1993-94 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आयातों में भी अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के अनुरूप वृद्धि हुई है। लेकिन भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषप्रद है।

— कुछ क्षेत्रों में व्यक्त की गई ये आशंकाएं कि हमारी व्यापार नीति से अनाथश्रमिक रूप से आयात बढ़ेगा तथा अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी, पूर्णतया निराधार सिद्ध हुई है। उदारीकरण और खुलेपन की नीति ने वस्तुतः हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है। अस्सी के दशक के उत्तरार्द्ध में मात्र लगभग 60 प्रतिशत की तुलना में अब आयात के 90 प्रतिशत से अधिक का वित्तपोषण निर्यात की आमदनी से होता है। चालू खाते पर विदेशी घाटा 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से अधिक था। इसके 1994-95 में 1/2 प्रतिशत से कम हो जाने की आशा है।

— उपरोक्त संकट के समय, हमारा विदेशी ऋण प्रतिवर्ष 8 बिलियन डॉलर की दर से बढ़ रहा था। 1993-94 में विदेशी ऋण में वृद्धि को घटाकर एक बिलियन डॉलर से कम कर दिया गया। 1994-95 की प्रथम छमाही में हमारे विदेशी ऋण के स्टॉक में वस्तुतः लगभग 300 बिलियन डॉलर की कमी हुई है।

— हमारे विदेशी मुद्रा का भण्डार जून 1991 में कम होकर मात्र एक बिलियन डॉलर तक रह गया था। 10 मार्च, 1995 को यह 20 बिलियन डॉलर से अधिक था।

— प्रारंभिक संकट पर एक बार काबू पा लेने के बाद हमारी रणनीति का एक मुख्य तत्व

निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना था। हमने इस वायदे को पूरा कर दिया है। पिछले दो बजटों में हमने केन्द्रीय क्षेत्र में रोजगार और निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों पर आयोजना व्यय में बड़ी तेजी से वृद्धि की है। ग्रामीण विकास के लिए 1992-93 (ब.अ.०) में 3100 करोड़ रुपए के आबंटन को दुगुने से भी अधिक बढ़ाकर 1994-95 (ब.अ.) में 7000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया था। इसी अवधि में, प्रारंभिक शिक्षा के लिए आबंटन में 84 प्रतिशत की, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आबंटन में 78 प्रतिशत की तथा स्वास्थ्य के लिए आबंटन में 91 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

4. ये संकेतक अपेक्षाकृत कम समय में उल्लेखनीय व्यापक आमूलचूल परिवर्तन को प्रमाणित करते हैं हमें चार वर्ष पहले विरासत में एक लगभग चरमराई हुई अर्थव्यवस्था मिली थी। हमने उसे एक ऐसी अर्थव्यवस्था में रूपान्तरित कर दिया है जो कृषि और औद्योगिक उत्पाद में तीव्र वृद्धि, देशी निवेश में तीव्र पुनरुद्धार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निरंतर वृद्धि, रोजगार में नवीकृत वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा की संतोषप्रद स्थिति को दर्शाती है। यह प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंहराव के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई दूर-दर्शितापूर्ण आर्थिक नीतियों और हमारे किमानों और औद्योगिक कामगारों, हमारे प्रबन्धकों तथा नियंतकों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम है। सर्वाधिक उत्साहवर्धक बात तो यह है कि मुधारों के समर्थन में व्यापक राष्ट्रीय एकमत उभरा है, एक ऐसा एकमत जो मुधार के पथ पर सतत गतिशीलता तथा निश्चित रूप से आगे बढ़ने की हमारी नीति का समर्थन करता है।

5. हम काफी लम्बा रास्ता तय कर चुके हैं, लेकिन यात्रा अभी अधूरी है। अपनी उपलब्धियों को और ठोस बनाने तथा अर्थव्यवस्था को बेहतर निष्पादन की ओर आगे बढ़ाने के लिए हमें कई क्षेत्रों में अपने प्रयासों को द्विगुणित करना होगा। यह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए व्यावहार्य भी है तथा आवश्यक भी। कराधान, व्यापार, औद्योगिक नीतियों और वित्तीय क्षेत्र में मुधारों के अच्छे परिणाम निकले हैं। उन्हें यथा-योजनाबद्ध रूप से पूरा किए जाने की जरूरत है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके। कृषि में आगे विस्तार में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करना होगा। सरकारी क्षेत्र को पुनर्गठित करना होगा। औद्योगिक संबंधों में श्रम के अभिनियोजन में और अधिक लचीलापन लाना होगा। सामाजिक सेवाओं के लिए सुपुर्देशी प्रणालियों को आधुनिक बनाना होगा, दोषों का निवारण करके और

लागत की प्रभावशीलता का संवर्धन करके निवेशकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पूंजी बाजार मुधारों को अधिक व्यापक तथा गहन बनाना होगा। बीमा सेवाओं को अत्यधिक मुलभ बनाने तथा प्रतिस्पर्धी और सक्षम ग्राहक-उन्मुख सेवाओं के संवर्धन के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र के मुधारों को जारी रखना होगा। हमें इन सभी क्षेत्रों में अवश्य ही आगे बढ़ना होगा।

6. कुछ कमजोरियां भी उभर कर सामने आई हैं और जिनकी ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राजकोपीय सुदृढ़ीकरण में प्रारंभिक सफलताओं के बाद, आगे प्रगति और भी दुसाध्य सिद्ध हुई है। राजकोपीय घाटा 1993-94 में तेजी से बढ़ा और घाटे पर दबाव 1994-95 में भी बना रहा। इन स्थितियों का सामना दृढ़ निश्चयी कार्रवाई करके किया जाना चाहिए। यदि हम उपलब्ध राजस्व को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक परियोजना तथा कार्यक्रम के लिए निधि की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, तो हम केवल अत्याधिक मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों को ही बढ़ावा देंगे जिससे निवेश बन्द हो जायेगा और निधियों के अभाव में पड़ी अपूर्ण परियोजनाओं में वृद्धि होगी। इस प्रकार के दृष्टिकोण से तो सामाजिक न्याय के साथ विकास के हमारे मूल उद्देश्य के लिए खतरा ही उत्पन्न होगा क्योंकि गरीब लोगों को ही इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति तथा रोजगार अवसरों में धीमी वृद्धि से नुकसान होगा। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगामी वर्षों में भी राजकोपीय अनुशासन अधिक बेहतर हो।

7. मुद्रास्फीति पुनः एक गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। हम मुद्रास्फीति की दर को 1991 की 17 प्रतिशत की उच्चतम दर से कम करके 1993 के मध्य में लगभग 7 प्रतिशत तक लाने में सफल हुए हैं लेकिन अब से मुद्रास्फीति में फिर से वृद्धि हुई है और इस समय यह 11 प्रतिशत से अधिक है। यह वृद्धि कई कारणों से हुई है। एक कारण पिछले तीन वर्षों में उगाही मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि है। दूसरा कारण चीनी, कपास तथा तेलहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन की कमी होना है। राजकोपीय घाटे का अपेक्षित स्तर से उच्चतर स्तर पर बने रहना भी स्फीतिकारी दबाव के बढ़ने का एक कारण रहा है। इन समस्याओं को स्वीकार करने हुए हम आगामी वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर मुद्रास्फीति का सामना करेंगे।

8. मुद्रा पूति की वृद्धि को कम करने के लिए मौद्रिक नीति को पहले ही सख्त कर दिया गया है - बचतों को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बैंक की जमा राशियों पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। विदेशी मुद्रा की बेहतर स्थिति का लाभ उठाते हुए महत्वपूर्ण अत्यावश्यक जिनमें जैसे चीनी, कपास, दालें और खाद्य तेलों का शून्य या कम शुल्कों के साथ मुक्त रूप से आयात की अनुमति दी गई है ताकि मुद्रास्फीतिकारी दबाव को कम किया जा सके। हम

इन वस्तुओं की कीमतों के दबाव को संतुलित करने की दृष्टि से गेहूं और चावल की खुले बाजार में लगातार बिक्री करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉकों का भी फायदा उठा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया गया है और इस के जरिए आपूर्ति को चीनी तथा खाद्य तेलों का अपेक्षित आयात करके और बढ़ाया जा रहा है। आने वाले वर्ष में भी, हम गेहूं, चावल तथा खाद्य तेलों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेंगे। टैरिफ और व्यापार नीतियों में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तार किया जाएगा कि औद्योगिक उत्पादों की देशी कीमतों में अनावश्यक वृद्धि न हो। उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ किया जाएगा तथा सरकार अवरोधक व्यवहार तथा जमाखोरी को नियंत्रित करने में सतर्क रहेगी। मेरे राजस्व प्रस्ताव, जिन्हें मैं कुछ देर बाद प्रस्तुत करूंगा भी आम उपभोक्ता वस्तुओं में मुद्रास्फीति को रोकने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं।

9. संभावित कमजोरी का एक दूसरा क्षेत्र आधारभूत संरचना है। यदि हमारा लक्ष्य 7 से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना है, जिसे अन्य देशों ने प्राप्त कर लिया है और जो हमारे बढ़ते हुए श्रमिक बल के लिए आवश्यक नौकरियां उपलब्ध करा सकता है, तो हमें विद्युत, सड़कों, पत्तनों, सिंचाई, रेलवे, तथा दूरसंचार जैसे आधारिक संरचना के प्रमुख क्षेत्रों में और अधिक निवेश तथा कार्यक्षमता को बढ़ाना होगा। कुशल वित्तीय प्रबंध ही इस क्षेत्र में प्रगति की कुंजी है। आधारभूत संरचना की पर्याप्त और गुणात्मक आपूर्ति अनिवार्यतः इन क्षेत्रों की वित्तीय व्यवहार्यता पर निर्भर है जो कि लागत की समुचित भरपाई वाली नीतियों के अग्रण होने पर आश्रित होता है। विद्युत का उदाहरण लें। बहुत सी राज्य सरकारें राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय कमजोरी के कारण विद्युत उत्पादन में नए निवेश की वित्त व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। विद्युत उत्पादन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार की पहल का लाभ उठाते हुए, बहुत सी राज्य सरकारें इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के निवेशक विद्युत क्षेत्र में निवेश करने के लिए उस समय तक इच्छुक नहीं हैं जब तक कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र के उत्पादकों को पुनः आश्वस्त करने के लिए गारंटियां और प्रति-गारंटियां नहीं देती कि जितनी विद्युत का वे उत्पादन करेंगे उसका उन्हें पूरा भुगतान किया जाएगा। ऐसी प्रति-गारंटियां केवल तभी तर्कसंगत होंगी जब उन्हें अस्थायी काम-चलाऊ व्यवस्था के रूप में देखा जाए जिसके दौरान राज्य विद्युत बोर्ड अपनी संस्थात्मक संरचना, प्रचालन पद्धतियों तथा मूल्य-निर्धारण नीतियों में आवश्यक सुधार करें। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में हम इस वास्तविकता से बच नहीं सकते कि विद्युत उपभोक्ताओं को इसकी लागत का भुगतान करना चाहिए। यही मानदण्ड अन्य आधारभूत संरचना क्षेत्रों पर भी लागू होता है। एक बार वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित

हो जाने पर हम इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के निवेशों में तब-प्रवाह की आशा कर सकते हैं।

10. अब मैं सामाजिक समता तथा निर्धनता विचारण के कुछ मुद्दों की चर्चा करूंगा। अपने पहले ही बजट भाषण में मैंने इस बान पर जोर दिया था कि आर्थिक विकास और पुनर्संरचना स्वयं में ही साध्य नहीं है। वे सामान्य नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के साधन मात्र हैं। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यह चिन्ता शुरु से ही हमारी रणनीति का केन्द्र बिन्दु रही है। अपने देश और साथ ही साथ पूरे विश्व के अनुभव से यह परिलक्षित होता है कि तेज और व्यापक आधार का विकास ही गरीबी हटाने की प्रचूक औषधि है। हमारे आर्थिक सुधारों का लक्ष्य वस्तुतः इसी उद्देश्य की प्राप्ति है। हम यह भी मानते हैं कि हमारे समाज के कुछ सबसे गरीब तथा कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने में समय लगेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे भी गीघ्र ही लाभ प्राप्त करने लगें, हमने ग्रामीण विकास, रोजगार-सृजन, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों तथा सामाजिक क्षेत्र के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों को अधिक सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। पिछले तीन वर्षों में तेजी से बढ़ते हुए आर्थिक विकास के साथ-साथ इन कार्यक्रमों का बेरोजगारी तथा गरीबी हटाने से वांछित प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रोजगार में तीन वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से विस्तार हो रहा है। कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी 1991-92 में संकट के समय कम हो गई थी। 1993-94 तक यह मजदूरी बढ़कर संकट-पूर्व स्तरों से अधिक हो गई थी। जीवन-मरण के आंकड़ों की उपलब्ध सूचना, जैसे अशांति मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर, से भी 1991-92 के बाद सामान्य जीवन-स्तर में स्पष्ट सुधार होने का पता चलता है।

11. संदेश स्पष्ट है। हमारे समाज में युगों पुरानी गरीबी के बोझ को हटाने का कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। हमें एक ओर विकास, निवेश और आधुनिकीकरण को बढ़ाने तथा दूसरी ओर निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाने की द्विमार्गी रणनीति को चालू रखना होगा। इस बजट में केन्द्रीय योजनागत आवंटन तथा कर प्रस्ताव इस रणनीति के दोनों तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रस्तावों की चर्चा करने से पहले मैं समाज के कमजोर वर्गों के लिए आय-अर्जक अवसरों को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुरू किए जाने वाले कुछ नवीन योजनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

12. कृषि में सरकारी निवेश की अपर्याप्ता आज एक सामान्य चिन्ता का विषय है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जिम्मेदारी राज्यों की है, लेकिन बहुत से राज्यों ने कृषि की आधारभूत संरचना में निवेश पर ध्यान नहीं दिया है।

बहुत सी ग्रामीण आधारभूत संरचना वाली ऐसी परियोजनाएँ हैं जो शुरू तो की गई हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में अधूरी पड़ी हुई हैं। वे ग्रामीण जनसंख्या की संभावित आय तथा रोजगार में बहुत बड़ी हानि की परिचायक हैं। ग्रामीण आधार्मिक संरचना से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की बढ़ावा देने हेतु, मैं अप्रैल, 1995 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अन्तर्गत एक नयी ग्रामीण आधार्मिक संरचनात्मक विकास निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस निधि से मध्यम और लघु मिचबाई, मृदा संरक्षण, जल संभरण प्रबंध तथा अन्य प्रकार की ग्रामीण आधार्मिक संरचना से संबंधित चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा वापसी-अदायगी तथा व्याज की गारंटी दिए जाने पर परियोजना-विशेष के आधार पर ये ऋण दिए जाएंगे। ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कम से कम समयावधि में पूरी की जा सकें। निधि के लिए संसाधन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जुटाए जाएंगे, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बात के निर्देश दिए जायेंगे कि उतनी राशि का अंशदान करें जितना कि अपेक्षित कृषि उधार हेतु प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देने के लक्ष्य से कम हो बशर्ते कि वह राशि बैंक की निवल ऋण राशि के 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो। ग्रामीण आधार्मिक संरचना वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इससे 2,000 करोड़ रुपए की राशि सृजित होने की आशा है।

13. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नागरिक हमारे ग्रामीण समाज के निर्धनतम सदस्य हैं। जनजातीय बहुलता वाले एक सौ जिलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अनुसूचित जनजातियों को ऋण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहकारिताओं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनन्य ऋण व्यवस्था प्रदान करेगा। वर्ष 1995-96 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगमों द्वारा अधिनिर्धारित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितियों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी करेगा। यह राशि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। जिसमें खेती और खेती-भिन्न दोनों प्रकार के कार्यों में लगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभान्वितियों की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

14. खादी और ग्रामोद्योग हमारे ग्रामीण लोगों को खेती-भिन्न अर्जन के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। मैं एक नई योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली द्वारा खादी और ग्रामोद्योग प्रयोग को संकाय आधार पर 1,000 करोड़ रुपये प्रदान

किए जाएंगे तथा आयोग सीधे अथवा राज्य स्तरीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से व्यवहार्य खादी और ग्रामोद्योग एककों को अनुराशि उधार देगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा आयोग द्वारा खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों को दिए जाने वाले इन ऋणों के लिए गारंटी क्रमशः केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी।

15. हथकरघा क्षेत्र में लाखों निर्धन वृत्तकारों को रोजगार मिलता है। इस समय, नाबार्ड द्वारा इस क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाला पुनर्वित्तपोषण जिला और राज्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण तक सीमित है। अब से, नाबार्ड वाणिज्यिक बैंकों को भी पुनर्वित्तपोषण प्रदान करेगा जिससे वे सहकारी हथकरघा संस्थाओं को ऋण दे सकें। पिछले वर्ष आरम्भ की गई स्कीम के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा केन्द्रों तथा गुणवत्ता प्राप्त रंगाई एककों को दिये जाने वाले ऋणों के प्रवाह को तेज करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

16. हमारे लघु उद्योग 14 मिलियन कामगारों को नियोजित करते हैं तथा इन उद्योगों का हमारे कुल विनिर्माण उत्पादन में हिस्सा 40 प्रतिशत और हमारे निर्यात में हिस्सा 35 प्रतिशत है। इस सक्रिय क्षेत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए और इसकी सहायता की जानी चाहिए जिससे यह क्षेत्र विकास, रोजगार सृजन तथा निर्यात के माध्यम से आत्मनिर्भरता संबंधी लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में एक प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की जाएगी जिससे उन उत्कृष्ट परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके जिनका उद्देश्य लघु उद्योगों की निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करना है। इस निधि के लिए निर्धारित प्रारम्भिक राशि 200 करोड़ रुपए होगी। यह वित्तीय सहायता जो कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा पात्र लघु एककों को सीधे प्रदान की जाएगी, ऋणों अथवा निवेश किसी भी रूप में हो सकती है।

17. 10 लाख रुपए से कम पूंजी वाली परियोजनाओं वाले तथा 5 लाख से कम (पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मामले में 15 लाख) जनसंख्या वाले स्थानों में स्थित अत्यन्त लघु एककों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1987 में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना की स्थापना की गई थी। मैं राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना का विस्तार सभी अत्यन्त लघु एककों तक करने का प्रस्ताव करता हूँ, चाहे ये एकक महानगरीय क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी स्थान पर स्थित हों। इसके अतिरिक्त, इस योजना के विषय क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विविधीकरण को शामिल किया जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा

संचालित इस स्कीम का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार तथा मिडबी द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता रहेगा।

18. बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऋण की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता लघु क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकार ने बैंकों के साथ परामर्श करके इस क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्धि में सुधार करने के लिए एक सात सूत्री कार्य योजना तैयार की है। इस योजना की एक प्रमुख विशेषता विशिष्ट बैंक शाखाओं की स्थापना किया जाना है जो ऐसे 85 निर्धारित जिलों में, जहां 2000 से अधिक पंजीकृत लघु एकक होंगे, लघु एककों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। सरकारी क्षेत्र के बैंक यह मुनिश्चित करेंगे कि 1995-96 के अंत से पहले 100 ऐसी समर्पित शाखाएं कार्य करने लगे।

19. हमारे देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास की गति को तेज करने की दृष्टि से एक नये उत्तर-पूर्वी विकास बैंक की स्थापना की जा रही है जो इस क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों तथा आधारभूत परियोजनाओं के सृजन, विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये धनराशि प्रदान करेगा। यह बैंक इसी क्षेत्र में स्थित होगा। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि. तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस बैंक की पूंजी के लिये प्रारम्भिक अंशदान किया जायेगा तथा इसके पश्चात् अन्य निवेशकों से अंशदान के लिये गुंजाइश रखी जायेगी।

20. हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिये आय अर्जन संबंधी अवसरों को बढ़ाने के इन उपायों के अतिरिक्त, मुख्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्धन लोगों के समान्य कल्याण के लिये चार दूरगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पहले कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों की आवास सुविधाओं की गंभीर कमी को दूर करना है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि ग्रामीण आवास के संबंध से इंदिरा आवास योजना नामक एक बड़ा कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। 1994-95 के दौरान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त किये गये बंधक मजदूरों को लगभग 4 लाख आवासीय मकान वित्तीय सहायता आधार पर प्रदान किये जाने की आशा है। 1995-96 में, आवास संबंधी लक्ष्य को दुगुने से भी अधिक करके 10 लाख एकक निर्धारित किया जा रहा है। इस तरह की पहल से हम आगामी पांच वर्षों में 50 लाख ग्रामीण आवासीय एककों का निर्माण कर सकेंगे इससे

हमें ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवास सम्बंधी अत्यधिक कमी से निपटने के लिये दूरगामी सहायता मिलेगी।

21. निर्धन वर्ग में सर्वाधिक कठिनाइयों का सामना प्रायः वृद्ध और कमजोर लोगों को करना पड़ता है, जिन में से अधिकांश लोग रोजगार के अयोग्य हैं। उनके दुःख भरे अंतिम वर्षों में उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिये, एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके अन्तर्गत निर्धन और जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जायेगा। इस योजना के एक घटक के अन्तर्गत, निर्धनता रेखा से नीचे के वर्ग के 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 75 रुपये प्रति माह को राष्ट्रीय न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना के दूसरे घटक के अन्तर्गत परिवार के मुख्य आय स्रोत की मृत्यु होने पर निर्धन परिवार को 5000 रुपये की एक मृत राशि उत्तरजीवी लाभ के रूप में दी जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तीसरे घटक के अन्तर्गत, निर्धन परिवारों की महिलाओं के लिये पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर मातृत्व देखभाल हेतु पोषाहार देने का प्रावधान रखा गया है। अंततः इस योजना से, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लगभग 14 मिलियन जरूरतमंद लाभानुभोगियों को लाभ पहुंचेगा। इस योजना के लाभानुभोगियों में लगभग तीन-चौथाई महिलाओं के होने की संभावना है जिन्हें वृद्धावस्था, वैधव्य तथा मातृत्व आदि कारणों से सहायता की जरूरत है। केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित की जाने वाली इस योजना का पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्यों द्वारा संचालित किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये, इस योजना के व्ययों तैयार करने हेतु मैं एक समिति नियुक्त कर रहा हूँ।

22. जीवन बीमा निगम की एक नई सामूहिक जीवन बीमा योजना सामाजिक सहायता के इस पैकेज के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 70 रुपये के मासुकी वार्षिक प्रीमियम पर 5000 रुपये का बीमा कवच प्रदान किया जायेगा। गरीब परिवारों के लिये, इस प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार तथा इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी तथा लाभानुभोगी को प्रीमियम के 50 प्रतिशत भाग का अंशदान करना होगा। इस आर्थिक सहायता को प्रत्येक निर्धन परिवार के लिये एक पलिसी तक सीमित रखा जायेगा। अन्य लोगों के लिये, प्रीमियम पर कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पंचायतों के सक्रिय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों से सामाजिक बीमा और वचत को बढ़ा

पैमाने पर संवर्धन करना है। इसमें निर्धन परिवारों को उत्तरजीवी लाभ के साथ-साथ आंशिक रूप से आर्थिक सहायता वाली सुरक्षा का दूसरा आवरण प्राप्त होगा तथा लोगों में बचत करने की आदत पनपेगी। जीवन बीमा निगम इस योजना के अग्रे तैयार करेगा।

23. स्कूली बच्चों को भोजन का भोजन प्रदान करने संबंधी योजनाओं से न केवल बाल पोषाहार पर वार्षिक स्कूल में उपस्थिति पर भी हितकर प्रभाव पड़ता है। कुछ राज्य सरकारें स्कूल में भोजन का भोजन प्रदान करने संबंधी योजनाएँ चला रही हैं। इस सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर बल दिये जाने की नीति के अन्तर्गत तथा सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त खाद्य भंडारों को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं का चरणबद्ध विस्तार करने में भागीदार होने की इच्छुक हो। स्थानीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा एक समिति द्वारा बनाई जायेगी ताकि इस योजना को 1995-96 में लागू किया जा सके।

24. समग्र रूप से देखने पर, कृषि संबंधी आधारभूत संरचना के वित्तपोषण, हथकरघा और खादी तथा ग्रामीणों को बढ़ावा देने, ग्रामीण आवास का विस्तार करने तथा सामाजिक बीमा आरंभ करने के लिये की जा रही इन नई पहलों से हमारी रणनीति के निर्धनता-रोधी घटक को बहुत बल मिलेगा। इसके साथ ही, हम अपने आर्थिक सुधारों को भी जारी रखेंगे जिनमें हमें पहले ही उत्कृष्ट परिणाम मिल चुके हैं।

25. औद्योगिक, व्यापारिक तथा कर संबंधी सुधारों, जिनमें औद्योगिक उत्पादन, निवेश तथा निर्यात में दशनीय वृद्धि हुई है, को जारी रखा जायेगा तथा बुनियादी स्तर पर इन सुधारों के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। एक महत्वपूर्ण सकारात्मक स्थिति यह उत्पन्न हुई है कि विद्युत् तथा दूरसंचार जैसे आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने संबंधी अनेक प्रस्ताव प्राप्त होने लगे हैं। हम इस बात की सुनिश्चित करेंगे कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश का प्रवाह गतिशीलता से हो। पूंजी बाजारों में सुधारों का तेजी में लागू किया जा रहा है। पूंजी बाजारों के प्रभावशाली विनियमन के लिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) को शक्तियाँ प्रदान करने के लिये हाल ही में 'सेबी' अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इस वर्ष के उत्तरार्ध में केन्द्रीय निर्वपागार स्थापित करने के लिये हमारा विधान लाने का प्रस्ताव है। हम वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से संबंधित अपने प्रयास जारी रखेंगे।

26. पिछले वर्ष मैंने अपने भाषण में बीमा क्षेत्र में सुधारों संबंधी समिति की रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था तथा संकेत दिया था कि हम सुधारों की भावी दिशा पर व्यापक एकमत तैयार करेंगे। पहले कदम के रूप में, मैं बीमा उद्योग के लिये एक स्वतन्त्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। इस संबंध में शीघ्र ही विचार लाया जायेगा।

27. अब मैं 1994-95 के संशोधित अनुमानों का संक्षेप में उल्लेख करूँगा।

28. वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 1,51,699 करोड़ रुपये का था। अब यह व्यय बढ़कर 1,62,272 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है अर्थात् इसमें 10,573 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

29. चालू वर्ष के बजट अनुमानों में आयोजना व्यय के लिये 46,582 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया था। राज्य आयोजनाओं और मंद व्यवस्थाओं की स्थानीय क्षेत्र योजना के लिये अतिरिक्त आबंटन संबंधी अतिरिक्त सहायता को पूरा करने के लिये यह राशि बढ़ाकर 48,761 करोड़ रुपये की जा रही है।

30. चालू वर्ष में 1,13,511 करोड़ रुपये का आयोजना-भिन्न व्यय का प्रावधान किया गया है जो बजट अनुमानों की तुलना में 8,394 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। खाद्य और उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिये संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों के संशोधन में विलम्ब होने के कारण खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के प्रावधान में 1,100 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि करनी पड़ी है। आयत की आवश्यकता को पूरा करने तथा पिछले बकायों का निपटारा करने के लिये उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता बजटीय स्तर से 1,166 करोड़ रुपये बढ़ाई जा रही है। इस वर्ष लघु बचत योजनाओं से संग्रहण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में संशोधित अनुमानों में 4,497 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

31. बजट अनुमानों में सकल कर राजस्व का अनुमान 87,136 करोड़ रुपये लगाया गया था। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि हमारे कर सुधारों ने अप्रत्याशित प्रभाव दर्शाना प्रारंभ कर दिया है और सकल कर राजस्व बजट अनुमानों से 2,695 करोड़ रुपये अधिक है, जो वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में 89,831 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह कर सुधार की हमारी नीति को सत्य सिद्ध करता है और यह राजस्व विभाग के कठोर परिश्रम और समर्पण भावना के प्रति एक आभार प्रदर्शन भी है, जिसके विपुल प्रयासों के बिना यह परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

32. वापसी-अदायगी को घटाकर विदेशी ऋण 4,279 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 3,947 करोड़ रुपये आंका गया है।

33. यद्यपि कर संग्रहण और अन्य कर्ज-भिन्न प्राप्तियां बजट में की गयी व्यवस्था में अधिक हुआ है, फिर भी इसके लाभ आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय में अत्यधिक वृद्धि द्वारा लघु भारित हो गए हैं। राजकोषीय घाटों का मूल रूप से वजतीय अनुमान 54,915 करोड़ रुपये अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आंका गया था। संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 61,035 करोड़ रुपये बैठता है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.7 प्रतिशत है। तथापि इस गिरावट का लगभग तीन-चौथाई भाग, लघु बचत संग्रहणों, जिसका 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है, में असधारण वृद्धि के कारण है। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे में गिरावट का प्रमुख हिस्सा केन्द्र सरकार के बड़े हुए व्यय के कारण नहीं है बल्कि बजट अनुमानों की तुलना में अधिक लघु बचतों का ही प्रतिबिम्ब है, जो राज्यों को ऋण रूप में दिया जाता है। अगर इस तत्व को छोड़ दिया जाये तो केन्द्र का राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के बजट लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 6.2 प्रतिशत होगा।

34. दसवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने वर्ष 1995-2000 के पांच वर्षीय अवधि के लिये 26 नवम्बर, 1994 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में राज्यों को किये जाने वाले अंतरणों में काफी वृद्धि की सिफारिश की है। केन्द्र के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होने के बावजूद, सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इन्हें वर्ष 1995-96 में कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत सुदृढ़ और अंतरणों के आधार पर केन्द्र से राज्यों को निधियों का प्रवाह वर्ष 1994-95 में 28,832 करोड़ रुपये में लगभग 22 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 1995-96 में 35,055 करोड़ रुपये हो जायेगा। हमें आशा है कि राज्य प्रतिरिक्त संसाधनों का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिये करेंगे जिनके लिये वे जारी किये जाने हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं के लाभ वांछित लाभान्वीभिषियों तक पहुंचे।

35. मैं अब वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों की ओर आता हूं। कुल व्यय का अनुमान 1,72,151 करोड़ रुपये लगाया गया है। केन्द्र सरकार के बजट में केन्द्रीय और राज्य आयोजनाओं के लिये वर्ष 1995-96 में 48,500 करोड़ रुपये की कुल बजट सहायता का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों के स्तर में 1,918 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाती है।

36. वर्ष 1995-96 की केन्द्रीय आयोजना के कुल परिव्यय को वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों में 70,141 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 78,849 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 1995-96 की केन्द्रीय आयोजना के लिए

बजतीय सहायता वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों से 27,278 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28,994 करोड़ रुपये कर दी गई है। शेष राशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकारों क्षेत्र के उद्योगों द्वारा उनके आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में की जाएगी जो कि कुल आयोजना परिव्यय का 63 प्रतिशत होगा जबकि 1994-95 के बजट अनुमान में यह 61 प्रतिशत था।

37. मैं वर्ष 1994-95 के बजट अनुमान में 19,304 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1995-96 के बजट अनुमान में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय आयोजना सहायता के रूप में 19,506 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रधान कर रहा हूं। यह कहना संगत होगा कि 1994-95 के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना अंतरण में नवें वित्त आयोग के निर्णयों पर आधारित 2,680 करोड़ रुपये शामिल हैं। दसवें वित्त आयोग ने आयोजना खातों में किसी अंतरण का मुआव नहीं दिया है। अतः केन्द्र द्वारा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विवेकाधीन आयोजना अंतरण को 1994-95 में 16,624 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1995-96 में 19,506 करोड़ रुपये कर दिया है जो 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। इस राशि को दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को किए जाने वाले अंतरणों में भारी वृद्धि को पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।

38. ऐसे कार्यक्रमों, जो सीधे निर्धनों को लाभ पहुंचाते हैं, को प्राथमिकता देने की हमारी नीति के अनुरूप, केन्द्रीय आयोजना को दी जाने वाली बजतीय सहायता को ग्रामीण विकास, रोजगार और निर्यतनता दूर करने के कार्यक्रमों तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों पर केन्द्रित किया जा रहा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, सुधार प्रक्रिया से ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए प्रत्यक्षतः लक्षित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को विशेष बल प्राप्त हुआ है और योजना परिव्यय में वृद्धि हुई है। पिछले बजट में, ग्रामीण विकास विभाग के लिए परिव्यय को वर्ष 1992-93 में दो वर्ष पहले रखी गई 3,100 करोड़ रुपये की बजट राशि को दुगुने से भी अधिक बढ़ाकर 7,010 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 1995-96 के लिए इस आवंटन को और बढ़ाकर 7,700 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इससे हम ग्रामीण विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के 30,000 करोड़ रुपये की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे। यह अनुमान है कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों ने वर्ष 1991-92 में लगभग 800 मिलियन मानवदिवसों का रोजगार सृजित किया। वर्ष 1995-96 में इन कार्यक्रमों द्वारा रोजगार के 1290 मिलियन मानवदिवस सृजित करने का अनुमान है।

39. वर्ष 1995-96 की वार्षिक आयोजना कृषि क्षेत्र में उत्पादकता सुधारने और बागवानी जैसी अधिक मूल्य

दिलाने वाली फार्म स्कीमों आदि द्वारा कृषि पद्धतियों में विविधता लाने परबल देती रहेगी। ऋण संबंधी जटिलताएँ, विस्तार संबंधी सहायता, विपणन और प्रमोशन मुविधायें प्रदान करने के लिए सहकारिताओं का पुनरुद्धार करने हेतु बन दिया जाना हमारा एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। सहकारिताओं के माध्यम से कृषि ऋण का प्रवाह वर्ष 1994-95 में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अनुमान की तुलना में वर्ष 1995-96 में 14,000 करोड़ रुपए होने की परिकल्पना की गई है। महिलाओं के लिए 220 सहकारी समितियों और कमजोर वर्गों के लिए 330 सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुमान है कि 38,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र को ट्रिप सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। एकीकृत कोट प्रबंध, जो पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल है, का विस्तार किया जाएगा और 50,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 1500 प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। गहन मत्स्य-पालन के अंतर्गत 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाने का अनुमान है।

40. सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शैक्षणिक अवसरों पर प्रसार अनिवार्य है। अल्पविकसित क्षेत्रों के बावजूद वर्ष 1995-96 में शिक्षा के लिए आयोजना परियोजना वर्ष 1994-95 में 1,541 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 1,825 करोड़ रुपए किया जा रहा है। हमारे समाज में महिलाओं और बालिकाओं की स्थिति को विशेष रूप से सुधारने के लिए बुनियादी शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बुनियादी शिक्षा के लिए परियोजना में 24.5 प्रतिशत की काफी वृद्धि करके 651 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आपरेशन अकबोर्ड के अंतर्गत 100 बच्चों से अधिक नामांकित वाले प्राथमिक विद्यालयों को एक तीसरा शिक्षक मुह्यत किया जा रहा है। ऑपरेशन अकबोर्ड के लिए आवंटन में वर्ष 1995-96 के लिए 30 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्तियों के लिए आवंटन वर्ष 1994-95 में 105 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 145 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह और अधिक योग्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने में सहायक होगा। राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए भारत सरकार उन सभी शर्तों को ध्यान में रखे बिना, जिन पर केन्द्रीय सरकार को यह सहायता प्राप्त होती है, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राप्त सभी विदेशी सहायता राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में दे रही है।

41. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के लिए संयुक्त आयोजना परियोजना को बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 2,251 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्ष 1995-96 के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए आवंटन 32 प्रतिशत बढ़ाकर 139 करोड़ रुपए किया जा रहा है ताकि जनजातीय क्षेत्रों और उत्तरपूर्वी राज्यों, जहाँ मलेरिया की जनसंख्या एक स्थानीय महामारी रही है, को उच्च प्राथमिकता देते हुए 163 मिनिमम लोगों को इस व्याधि से मुक्ति

प्रदान की जा सके। वर्ष 1995-96 में कुल नियंत्रण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य वर्ष 2000 तक इस रोग का फैलना समाप्त करना है, के लिए 80 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए 160 करोड़ रुपए और 9,577 ग्रामीण उप-केन्द्रों के अनुरक्षण के लिए 190 करोड़ रुपए सहित ग्रामीण क्षेत्रों से सीधे संबंध रखने वाले परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 726 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है।

42. वर्ष 1995-96 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय 1,23,651 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा के लिए परियोजना 25,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वर्ष 1995-96 में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,400 करोड़ रुपए निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, किमानों को फासफेटी और पोटाशी उर्वरकों की सस्ती आपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं और इस प्रकार कुल प्रभावी उर्वरक आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 5,900 करोड़ रुपए किया जा रहा है। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए 5,250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

43. राजस्व प्राप्तियों की ओर आने पर, कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व का अनुमान 1,03,762 करोड़ रुपए लगाया गया है। राज्यों को करों के हिस्से का भुगतान 29,388 करोड़ रुपए आका गया है। कर-भिन्न राजस्व सहित, केन्द्र को निवल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 1994-95 में 86,084 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 1,00,787 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

44. पूँजी प्राप्तियों के क्षेत्र में, परंपरागत बाजार उद्यारों का अनुमान 3,700 करोड़ रुपए लगाया गया है अन्य मध्यावधिक तथा दीर्घवधिक ऋण 19,000 करोड़ रुपए तथा अल्पावधिक ऋण 4,387 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। निवल विदेशी सहायता का अनुमान 4,456 करोड़ रुपए लगाया गया है। पिछले वर्ष की भांति, सरकार का सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया को जारी रखने का इरादा है। बजट अनुमानों में विनिवेश से 7,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति की व्यवस्था की गई है, जो कि वर्ष 1994-95 के लिए संशोधित अनुमानों में दिए गए 5,237 करोड़ रुपए के आंकड़े से काफी अधिक है।

45. प्राप्तियों और व्यय में अन्य परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, कराधान की मौजूदा दरों पर कुल प्राप्तियाँ 1,67,151 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जबकि कुल व्यय 1,72,151 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप 5,000 करोड़ रुपए का बजट घाटा होता है। वर्ष 1995-96 के लिए इन अनुमानों से उत्पन्न राजकोषीय घाटा 57,634 करोड़ रुपए होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद

का लगभग 5.5 प्रतिशत होगा। मैं इसे उद्भूत करता चाहता था परंतु संकुचन रखने हुए मैं मंजूर करता हूँ कि अगर मौजूदा वृद्धि की गति बनाई रखी जाती है तो इसी मात्रा में राजकोषीय घाटा आत्मसात किया जा सकता है।

भाग 'ख'

46. अब मैं वर्ष 1995-96 के कर संबंधी प्रस्तावों पर आता हूँ।

47. पिछले तीन वर्षों में हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के कानूनों में कई संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। कर प्रणाली को संशोधित करने के पिछले असंबद्ध प्रयासों के विपरीत, ये परिवर्तन कतिपय सामान्य सिद्धांतों, जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, द्वारा मार्ग निर्देशित कर-सुधार के मध्यमावधिक कार्यक्रम का एक हिस्सा थे। हमने ऐसा ढांचा बनाना चाहा, जो साधारण हो, मध्यम स्तरीय कर दरों पर निर्भर करता हो, परंतु जिनका आधार व्यापक और बेहतर प्रवर्तन वाला हो, समानता के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी, गतिशील अर्थव्यवस्था विकसित करने के अनुरूप प्रोत्साहन और संकेत प्रदान करता हो।

48. प्रत्यक्ष करों का राजस्व जुटाने का एक अत्यधिक उचित रूप है, परंतु पूर्ववर्ती वर्षों में उच्च कर दरों का अनुभव दर्शाता है कि उच्च दरों से अधिक संग्रहण नहीं हुआ। यह सुचित करते हुए मुझे खुशी है कि दरें घटाने और उसके द्वारा अनुपाजन को प्रोत्साहित करने के हमारे निर्णय से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। व्यक्तिगत आय और निगम करों, दोनों को मिला कर, वर्ष 1994-95 में उनमें लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 1990-91 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1994-95 में 2.8 प्रतिशत हो गया है।

49. सीमा-शुल्क के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य आयात शुल्क की उच्च दरों को धीरे-धीरे कम करना था ताकि उत्पादन की लागत कम की जा सके तथा आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे घरेलू उत्पादकों को व्यवस्थित होने का उचित समय देते हुए प्रयोक्ता उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। वर्ष 1994-95 में भारतीय उद्योग का सुदृढ़ विकास, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करता है कि सीमाशुल्क संबंधी सुधार औद्योगिक उत्पादन को आवश्यक गतिशीलता प्रदान करने में सफल रहे हैं।

50. उत्पाद शुल्कों के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य संरचना को सरल बनाना, आधार को विस्तृत बनाना, ऐसे शुल्कों की उच्च दरें कम करना, जो कर-अपवर्जन को प्रोत्साहित करती हैं, जहां तक संभव हो मूलानुसार दरों की ओर अंतरित होना और 'मोडवाट' की व्यापकता में विस्तार करना था। ये

परिणाम वर्ष 1994-95 में उत्पाद-शुल्क राजस्व की प्रभाव-शाली वृद्धि से स्पष्ट हैं।

51. मैं इन परिणामों से पुनः आश्चर्यचकित हूँ कि कर-सुधारों की हमारी वृत्तिवादी नीति पूर्णतः सही सिद्ध हुई है। राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक उपायों के साथ अब मुझे विश्वास है कि हम एक ऐसी कर संरचना सृजित कर सकते हैं, जो उत्पादन और रोजगार की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करने हुए वृद्धिकारी राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करेगी।

52. अध्यक्ष महोदय, इस संक्षिप्त चर्चा के बाद मैं प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों का विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

53. मुझे संसद सदस्यों, श्रमिक संघों और ग्रन्थों से व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए अनेक प्रस्तावों का प्राप्त हुए हैं। हमारी सरकार ने ग्राम आदमी की वास्तविक आवश्यकताओं को अनुकूल रूप से सराहा है। अतएव, मैं आयकर के लिए छूट सीमा को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

54. हमें बचत के लिए प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस समय आयकर अधिनियम की धारा 80ड के अंतर्गत, कतिपय निविष्ट वित्तीय आस्तियों से व्याज और लाभों द्वारा होने वाली आय को 10,000 रुपये वार्षिक तक आयकर से छूट प्राप्त है। व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों द्वारा की गई घरेलू बचतों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, मैं इस सीमा को बढ़ाकर 13,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे बचतकर्ताओं को राहत तथा एक और प्रोत्साहन दोनों प्राप्त होंगे।

55. इन परिवर्तनों से, वित्तभोगी व्यक्ति को 55,000 रुपये की धन सीमा तक कोई कर अदा नहीं करना होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह सीमा और अधिक अर्थात् 58,000 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को 13,000 रुपये की अतिरिक्त छूट से लाभ प्राप्त होगा, अगर वह धारा 80ड के अंतर्गत बचत उपायों से होने वाली आय के लिए छूट का पूर्ण लाभ उठाता है। इस प्रकार कर-छूट प्राप्त आय सामान्यतया 68,000 रुपये और कामकाजी महिलाओं के लिए 71,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक पहुंच सकती है। इस सीमा से बाहर आने पर व्यक्ति ही कर अदा करना प्रारंभ करेगा और वह भी केवल संयत दरों पर।

56. अपर्याप्त आधारभूत संरचना हमारी आर्थिक प्रगति की एक मुख्य बाधा है। उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं ऐसी किसी भी उद्यम को, जो राजमार्गों, तीव्रगामी मार्गों और नए पुलों, विमानपत्तनों, नौपत्तनों और तीव्रगामी उन परिवहन

प्रणालियों के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं निमित्त, अनुरक्षित और प्रचालित करते हैं, पांच-वर्षीय करावकाश देने का प्रस्ताव करता हूं। यह करावकाश उन उद्यमों को उपलब्ध होगा, जो पहली अप्रैल, 1995 के बाद कार्य आरंभ करेंगे। ऐसे आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दीर्घाधिक वित्तपोषण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन के रूप में, मैं उन निवेशों के वित्तपोषण से प्राप्त होने वाली उनकी कर-योग्य आय के 40 प्रतिशत तक की कटौती देने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि यह राशि एक विशेष प्रारक्षित निधि में जमा की जाए।

57. आयकर अधिनियम की धारा 80-सक के अंतर्गत 31 मार्च, 1995 के पूर्व कार्य आरंभ करने वाले नए औद्योगिक उपक्रम, होटल तथा नौवहन प्रतिष्ठान, अगर वे कंपनियां हैं तो अपनी आय के 30 प्रतिशत अथवा अन्वये निगमेतर संस्थाएं हैं तो, अपनी आय के 25 प्रतिशत की कटौती के हकदार होंगे। यह प्रोत्साहन सहकारी समितियों को प्रथम 12 वर्षों के लिए और अन्वयों के लिए कार्यचालन के प्रथम 10 वर्षों के लिए उपलब्ध है। लघु उद्योगों की सहायता के विशेष उपाय के रूप में, मैं इस रियायत को उनके लिए और पांच वर्षों तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार, लघु उद्योग क्षेत्र में नए औद्योगिक उपक्रम, जो 31 मार्च, 2000 से पूर्व कार्य आरंभ करते हैं, इस रियायत के पात्र होंगे।

58. साफ्टवेयर के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है और यह निर्यात अर्जनों का संभावित गतिशील हिस्सा प्रदर्शित करता है। तथापि, साफ्टवेयर के निर्यातकर्ताओं ने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें धारा 80-जजड के अंतर्गत उपलब्ध कटौती वर्षानुवर्ष प्राप्त होती है जबकि वस्तुओं के निर्यात के लिए धारा 80 जजग असीमित है। मैं धारा 80 जजग की तरह धारा 80 जजड को भी उसी आधार पर रखने के उनके अनुरोध को स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

59. नई कर्मों और प्रौद्योगिकियों, जिनमें प्रायः अधिक जोखिम होता है, के विकास के संवर्धन के लिए उद्यम पूंजी निधियां एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती हैं। अनेक देशों के कर कानून ऐसी निधियों की आय को निधियों के पास कराधान से छूट देते हैं, परंतु उनके वितरण के बाद उन पर कर लगते हैं। भारत में इसी प्रकार उद्यम पूंजी निधि निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मैं, अनुमोदित उद्यम पूंजी निधियों अथवा उद्यम पूंजी कंपनियों द्वारा लाभार्ज और इक्विटी निवेशों से होने वाले दीर्घाधिक पूंजी अभिलाभों से प्राप्त होने वाली आय को कर में छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी उद्यम पूंजी निधियों को विगमिनि में संलग्न केवल असूचीबद्ध कंपनियों में ही निवेश करना अपेक्षित होगा। तथापि, शेयरधारकों को होने वाली आय पूर्णतः कर योग्य होगी।

60. स्वतंत्रता दिवस, 1994 को प्रधानमंत्री ने एकीकृत शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, शहरी विकास मंत्रालय एक राष्ट्रीय शहरी निर्धनता उन्मूलन निधि (एन.यू.पी. ई.एफ.) स्थापित कर रहा है। मैं इस निधि में किए जाने वाले अंशदान के संबंध में आय को शत-प्रतिशत कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं।

61. आयकर अधिनियम की धारा 80-प के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों की कुल आय से 20,000 रुपए की पृथक कटौती दी जाती है। मुझे विकलांग व्यक्तियों और कल्याण संगठनों से यह उल्लेख करते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन व्यक्तियों को दवाइयों और जीवन-निर्वाह उपकरणों की बड़ी हुई कीमत के कारण अतिरिक्त राहत की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकताओं को मानते हुए, मैं विकलांग व्यक्तियों के लिए कटौती के मौजूदा 20,000 रुपए के स्तर को बढ़ाकर 40,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

62. कई स्वैच्छिक राहत संगठनों ने अभ्यावेदन दिये हैं कि अत्यधिक विकलांगता, जैसे मंदबुद्धि वाले बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक, अपनी मृत्यु के बाद विकलांगों को अनुरक्षण प्रदान करने के बोझ के बारे में चिंता करके अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना करते हैं। मुझे यह अभ्यावेदन उचित प्रतीत होता है। इसलिए मैं विकलांग बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों की कर-योग्य आय से 20,000 रुपए तक की नई कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि यह राशि जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि जैसी किसी अनुमोदित स्कीम में जमा की जाए जिसमें माता-पिता अथवा अभिभावकों की मृत्यु के बाद विकलांग आश्रित के अनुरक्षण और देखभाल के लिए आवर्ती अथवा एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा सके।

63. कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए श्रमिक संघों द्वारा बहुत सी निधियों की स्थापना की गई है। इन निधियों का प्रयोग अधिवर्षिता, बीनारी अथवा मृत्यु की दशा में अथवा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए नकद लाभ प्रदान करने के लिये किया जाता है। मैं ऐसी निधियों से होने वाली आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

64. स्वतंत्रता दिवस, 1993 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना की गई है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देना है। मैं इस निगम की आय तथा साथ ही किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित इस प्रकार के निगमों की आय को आयकर से छूट

देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, आयकर अधिनियम की धारा 80-छ के अंतर्गत, इन निगमों को दिये गए दान के संबंध में भी कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

65. मानव संसाधन का उन्नयन उच्च प्राथमिकता का विषय है। मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, जहां पर ऐसी शिक्षा की सुविधाओं की कमी है। सरकारी निधिकरण के साथ-साथ, हमें इस उद्देश्य के लिए निजी अंशदानों को बढ़ावा देना है। 1993 में, मैंने विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की शैक्षणिक संस्थाओं को दिये जाने वाले दान को कर-योग्य आय से शत-प्रतिशत कटौती का लाभ दिया था। इस वर्ष, मैं प्रारंभिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जिलों में गठित की गई जिला साक्षरता समितियों को मिलने वाले दान पर शत-प्रतिशत कटौती प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी तथा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के हमारे प्रयासों में और तीव्रता आएगी।

66. परे विश्व में, राजस्व प्रशासन स्रोत पर कर की कटौती के क्षेत्र को बढ़ाकर, कर संबंधी आधार का विस्तार करते हैं। इससे अधिक लोग कर की परिधि में आ जाते हैं तथा कराधान की निम्न दरों को अपनाने में सहायता मिलती है। इससे सही आय की सूचना मिलने में भी सहायता मिलती है। बहुत से देशों में, व्यावसायिक तथा तकनीकी सेवाओं से होने वाली आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती कर ली जाती है। इस क्षेत्र में, आय संबंधी अधूरी सूचना देने को रोकने के लिये मैं आयकर अधिनियम में एक नया उपबंध जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं के लिये शुल्क के रूप में देय राशि पर 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी। यदि वित्त वर्ष के दौरान, सकल अदायगियां अथवा उधार की राशि 20,000 रुपये से कम हैं अथवा अदायगियां व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों द्वारा की जाती हैं तो स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जायेगी।

67. आयकर अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत, उविदाकारों को 10,000 रुपये से अधिक राशि की अदायगी करने पर स्रोत पर कर की कटौती कर ली जाती है। इस संंध में ऐसे कानूनी विवाद उत्पन्न हुए हैं कि क्या स्रोत पर काटे जाने वाले कर संबंधी उपबंध परिवहन संविदाओं, विज्ञापन संविदाओं, प्रसारण संविदाओं, टेलीकॉस्टिंग संविदाओं तथा खान-पान संबंधी संविदाओं पर भी लागू होंगे। और अधिक मुकदमेबाजी से बचने तथा कर अपवचन को रोकने के लिये, मैं इन मामलों में मुख्य संविदा के लिये 2 प्रतिशत की भौजवा दर

तथा उप-संविदा के लिये 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर ही कर की कटौती का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, स्रोत पर कटौती न किये जाने वाली सीमा, जो इस समय 10,000 रुपये है, को बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

68. म्यूचुअल फंडों अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों से होने वाली आय पर यद्यपि आयकर देय होता है परन्तु अधिकांश मामलों में इन पर स्रोत पर ही कर की कटौती नहीं होती। इसके कारण ऐसी आय की सूचना नहीं दी जाती अथवा आय की अधूरी सूचना दी जाती है। इस दुरुपयोग को रोकने तथा अन्य वित्तीय प्रपत्रों के प्रयोग में एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिये, मैं ऐसी आय पर कंपनियों के मामले में 20 प्रतिशत की दर से तथा अन्य सभी, जिनमें अलग-अलग व्यक्ति तथा हिन्दू अविभाजित परिवार शामिल हैं के लिये 15 प्रतिशत की दर से स्रोत पर ही कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। अनिवारियों अथवा अप्रतरीय निधियों को मिलने वाली मौजूदा कर संबंधी रियायतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निवासी यूनिट धारकों के मामले में, स्रोत पर कटौती अभी की जायेगी यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत देय आय को सकल राशि 10,000 रुपये से अधिक हो। यदि किसी ऐसी मौजूदा स्कीम के अन्तर्गत यूनिट जारी किये गये हों जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद निर्धारित राशि की अदायगी की व्यवस्था हो अथवा आय संबंधी अदायगी के लिये उत्तर-दिनांकित चेक पहले ही जारी किये जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में स्रोत पर कर की कटौती नहीं कजायेगी।

69. मैं बैंकों में सावधि जमा पर देशी कंपनियों को मिलने वाले व्याज से 20 प्रतिशत की दर से तथा इस पर अधिभार तथा व्यक्तियों और अन्य निगम-संस्थाओं को मिलने वाले व्याज 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर आय कर की कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह नया प्रावधान पहली जुलाई, 1995 को या इसके बाद जमा की गई धनराशियों पर ही लागू होगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शाखावार जमा की गई या अदा की गई व्याज की रकम 10,000 रुपये या इससे कम हो तो उस पर किसी कर की कटौती नहीं की जायेगी। इस प्रकार लघु जमा राशियों वाले व्यक्ति कर-कटौती की अपेक्षा से प्रभावित नहीं होंगे। जहां व्याज प्राप्तकर्ता की आयकर-योग्य नहीं होती, वहां कर की कटौती न करने को वर्तमान सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राथमिक ऋण समितियों, सहकारी भूमि बंधक बैंकों या सहकारी भूमि विकास बैंकों की सावधि जमा राशियों पर मिलने वाला व्याज इस प्रावधान के क्षेत्र से बाहर होगा।

70. आयकर अधिनियम के अध्याय 20ग से केन्द्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक निर्धारित सीमा, जो कि इस समय 10 लाख रुपये है, से आगे अचल सम्पत्तियों की पूर्वक्रय खरीद करें। अचल सम्पदा मूल्यों में होने वाले स्थानीय परिवर्तनों के संदर्भ में सभी अधिसूचित नगरों के लिये एक ही आर्थिक सीमा में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं अलग-अलग नगरों के लिये अलग-अलग आर्थिक सीमा निर्धारित करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

71. माननीय सदस्यों को यह मान्य है कि आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशियाँ काले धन का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तथापि, अधोषित आय का संबंध उन विभिन्न वर्षों से स्थापित किया जाता है जब वह आय अर्जित की गई थी और इस प्रकार कर-निर्धारण से अत्यधिक देरी होती है। इस प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाने के लिये मैं एक नई योजना का प्रस्ताव कर रहा हूँ, जिसके अन्तर्गत तलाशी करने के परिणामस्वरूप पता लगाई गई अधोषित आय का कर-निर्धारण अलग से 60 प्रतिशत की समान दर पर किया जायेगा। इस आदेश के विरुद्ध अपील सीधे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती है।

72. मूल्यहास के लिये कटौती देने के लिये ऐसी मशीनरी या संयंत्र की पृथक्-पृथक् मदों के लिये क्रय-वर्ष में शत-प्रतिशत की कटौती की जाती है जिसका मूल्य 5,000 रुपये से अधिक न हो। तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के अप्रतिष्ठित मूल्य शून्य माने जाते हैं। यह प्रावधान इसलिये शुरू किया गया था क्योंकि मूल्यहास में छूट देने के प्रयोजनों के लिये कम मूल्य की वस्तुओं का रिकार्ड रखने में कठिनाइयाँ महसूस की गई थीं। पहली अप्रैल, 1988 से आस्तियों के समूह की अवधारणा में परिवर्तन होने के बाद, एक समूह में आने वाली संयंत्र और मशीनरी की सभी मदें निर्धारित दरों पर मूल्यहास प्रदान करने के लिये एक साथ मिला दी जाती हैं। इसलिये इस प्रावधान के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि 5000 रुपये से कम लागत वाली मशीनरी या संयंत्र की मदें भी 'थोक आस्तियों' का भाग होगी तथा उन पर आयकर नियमों में विनिर्दिष्ट दर पर मूल्यहास की अनुमति दी जायेगी।

73. मैं यह प्रावधान करने के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ कि कर-योग्य आय की गणना केवल तब या व्यापारिक आधार पर की जाए। यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि कर-दाता केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए समय-समय पर यथा-अधिसूचित लेखा-मानकों का अनुपालन करेंगे। यह प्रावधान पहली अप्रैल, 1996 से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से लागू किया जाएगा।

74. बोनस शेयरों की बिक्री पर पूंजीगत अभिलाभ के परिकलन के कारण बहुत से विवाद उत्पन्न हुए हैं। स्थिति को सरल बनाने तथा विवादों से बचने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि पूंजीगत अभिलाभ करके परिकलन के लिए बोनस शेयरों की लागत शून्य समझी जाएगी।

75. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

76. मेरे प्रस्तावों का मुख्य जोर पहले से ही अपनायी जाने वाली कर-मुक्तियों की नीति को जारी रखना, भारतीय उत्पादकों के लिए निविष्टियों को लागत को कम करना, कर-संरचना को सरल बनाना, असंगतियों को कम करना, प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना, भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा अंश को जाने वाली कीमतें कम करना तथा इस प्रकार मुद्रा-क्षीति की संभावना को रोकना है।

77. पहले मैं आयात शुल्कों का उल्लेख करूँगा। 65 प्रतिशत के आयात शुल्क की वर्तमान ऊँची दर उद्योग प्रधान राष्ट्रों की तुलना में ही नहीं बल्कि अन्य विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत अधिक है। मेरा प्रस्ताव है कि इस ऊँची दर को कम करके 50 प्रतिशत तक लाकर चरणबद्ध कटौती की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

78. मशीनरी और पूंजीगत मान जैत्र हनारे उद्योग का एक अत्यावश्यक क्षेत्र है तथा नई नीतियों का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ा है, जिसके कारण इसमें अर्बन-नवम्बर 1994 में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं उपायों के एक पैकेज का प्रस्ताव करता हूँ जिससे मशीनरी तथा पूंजीगत मान पर प्रभा लागू आयात शुल्क संरचना और प्रतिक्रियुक्तित्वगत तथा सरल बनेगी, बहुत-सी असंगतियाँ दूर हो जाएँगी तथा उद्योगों को उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

* हम समय मशीनरी की मर्चों पर सामान्य आयात शुल्क की दर 25 प्रतिशत है लेकिन जेनरेटिंग सेटों तथा भारमापी मशीनरी जैसे अनेक पूंजीगत मान पर शुल्क की अपेक्षाकृत उच्च दर है। मेरा इन मदों पर भी शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत तक जाने का प्रस्ताव है।

* मशीनरी औजारों पर आयात शुल्क की दर इस समय 35 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत के बीच है। मेरा इन शुल्क दरों को समान रूप से 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जो कि मशीनरी के लिए सामान्य दर है। ऐसे मशीनी औजारों के पुर्जों पर भी सामान्यतया 25 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

* पूंजीगत माल के संघटकों पर सामान्यतया 25 प्रतिशत का आयात शुल्क लगता है लेकिन इलेक्ट्रानिक पुर्जों वाले संघटकों तथा मोटरवाहन पुर्जों के साथ अन्तर परिवर्तनीय संघटकों पर अपेक्षाकृत अधिक दरें लगती हैं। मेरा इन संघटकों पर शुल्क दर को कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

* यदि विनिर्माण उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है तो उसके लिए गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। मेरा परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अन्य यंत्रों पर लगने वाले आयात शुल्क के 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक की वर्तमान दरों को कम करके 25 प्रतिशत के एक समान स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। सामान्यतया ऐसे यंत्रों के पुर्जों पर भी यही दर लागू होगी।

79. इन प्रस्तावों से लगभग 80 प्रतिशत सामान्य मशीनरी (यांत्रिक और विद्युत दोनों), मशीनी, औजारों, यंत्रों और परियोजनाओं के लिए सीमाशुल्क दरों को 25 प्रतिशत पर एकीकृत किया जाएगा। उनसे पुर्जों और संघटकों से संबंधित असंगतियां दूर होंगी, वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे तथा इसकी लागत में कमी होने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

80. लौह तथा अलौह धातुएं पूंजीगत माल तथा बहुत से अन्य उत्पादों की प्रमुख निविष्टियां हैं जिनमें से अनेक का उत्पादन लघु उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इन मदों पर इस समय 50 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न शुल्क दरें लगती हैं। आदर्श रूप में, ऐसी सामग्रियों पर पूंजीगत माल की अपेक्षा अधिक शुल्क दरें नहीं लगनी चाहिए। लेकिन देशी धातु उत्पादकों को यथोचित संक्रमण अवधि देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मेरी लौह तथा अलौह धातुओं पर आयात शुल्क की दरों को कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। तांबा, जस्ता और शीशा जैसे अपरिष्कृत अलौह धातुओं के लिए, आयात शुल्क को कम करके 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। पुनर्वेल्लन (रिरोलिंग) के लिए लोहे और इस्पात के गर्म बेल्ड कायल पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। और जंगरोधी इस्पात के स्क्रैप पर इसे 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। स्पंज आयरन पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मैं बहुत से गैर-धात्विक खनिजों पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

81. मैं बॉल या रोलर बेयरिंग पर आयात शुल्क की संरचना को भी सरल बना रहा हूँ जिस पर इस समय

आकार, भार और किस्म आधार पर भिन्न-भिन्न शुल्क दरें लगती हैं। अब से सभी बॉल या रोलर बेयरिंगों पर 25 प्रतिशत — प्रति किया. 120 रुपए का एक समान शुल्क लगेगा। सशोधित कर संरचना में न्यूनबीजकीकरण और नमूने के प्रोत्साहन में कमी आने की संभावना है।

82. कपड़ा और वस्त्र सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं। फिर भी कच्चे माल और निविष्टियों पर हमारा आयात शुल्क काफी अधिक है जिसका इस्तेमाल मिथेटिक सूत, रेगा और कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए तथा इस संवेदनशील क्षेत्र में जारी स्फीतिकारी दबाव देखते हुए, मैं जाइलों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि डीएमटी/पीटीए की विनिर्माण लागत कम हो सके। मेरा डीएमटी पीटीए तथा एमईजी, पर जो कि पोलियस्टर फाइबर तथा पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण के अत्यावश्यक कच्चे माल हैं, आयात शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है। कैप्रोलैक्टम, जो कि नाइलोन का एक मूल कच्चा माल है, पर आयात शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इन परिवर्तनों से प्रयोक्ता उद्योगों के निवेश लागत में पर्याप्त कमी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तैयार उत्पादों की कीमतों में ये लाभ परिलक्षित हो सकें, मेरा मिथेटिक रेगों और फिलामेंट सूतों पर आयात शुल्क को कम करके सममूल्य पर 45 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

83. मेरा उद्योग में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले कतिपय रसायनों पर आयात शुल्क कम करने का भी प्रस्ताव है। इथिलीन तथा बेंजीन जैसे मूलभूत आपूर्ति स्टाक पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत किया जा रहा है। सोडा एश, कास्टिक सोडा तथा लाइनियर अल्काइल बेंजीन पर आयात शुल्क 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत किया जा रहा है। एकीलोनिट्राइल जैसे कतिपय रासायनिक मध्यवर्ती पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया जा रहा है। मेरा अलकोहल आधारित रासायनिक उद्योगों की सहायता करने के लिए शोरा पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। एलपीजी पर भी शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

84. इलेक्ट्रानिकी तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है जिससे लघु क्षेत्र में नियोजित, रोजगार और विकास की बड़ी संभावनाएं परिलक्षित होती हैं। अपने पिछले बजट में, मैंने इस उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्कों में अत्यधिक कटौत किया था। इस दिशा में अग्रणी उपाय के रूप में, मेरा विनिर्दिष्ट कच्चे माल तथा छोटे पुर्जों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत के मौजूदा स्तरों से कम करके 15 प्रतिशत के समान स्तर पर लाना, प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों

और कवर मॉनीटर ट्यूबों सहित इलेक्ट्रॉनिक संघटकों पर 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत, पापुलेटिड प्रिन्टेड सर्किट बोर्डों पर 50 प्रतिशत और 65 प्रतिशत से कम करके 35 प्रतिशत तथा कम्प्यूटरों पर 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मेरा इन्टिग्रेटेड सर्किटों और हार्ड डिस्क ड्राइवों पर आयात शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है जिससे इन उत्पादों के अलभ्य वस्तु बाजार (ग्रे मार्केट) में कमी होने की संभावना है। रंगीन टी वी की पिम्पर ट्यूबों पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। दूरसंचार अप्टिकल फाइबर केवल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, मेरा अप्टिकल फाइबर पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मेरा प्रणाली तथा अनुप्रयोग दोनों प्रकार के मापद्वेयर पर आयात शुल्क को कम करके उसे केवल 10 प्रतिशत के समान स्तर पर लाने का भी प्रस्ताव है। कर संरचना में इन परिवर्तनों से मुझे आशा है कि यह उद्योग भविष्य में और भी गतिशीलता दिखाएगा।

85. स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, पिछले वर्ष मैंने चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क की संरचना को सरल बना दिया था, कई प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को शुल्क की श्रदायगी से छूट दे दी थी तथा धर्मार्थ अस्पतालों के लिए छूट का लाभ उठाने की प्रमाणन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया था। चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए मैं छूट प्राप्त जीवन रक्षक तथा दृष्टि रक्षक उपकरणों के सभी पुर्जों को आयात शुल्क से पूरी तरह छूट देने का लाभ प्रदान कर रहा हूँ। पापुलेटिड पी सी बी जैसे अन्य शुल्क योग्य चिकित्सा उपकरणों के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों पर 15 प्रतिशत का आयात शुल्क लगेगा। मेरा लीनियर एक्सीलेरेटरों को पूरी तरह शुल्क मुक्त करने का भी प्रस्ताव है जो कि कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए अत्यावश्यक हैं। बहुत सी औषध मध्यवर्तियों पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

86. हमारे मुद्रण उद्योग के लिए अच्छे किस्म के कागज की आवश्यकता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना मजबूत आधार स्थापित कर सके। इसकी ध्यान में रखते हुए मेरा कागज पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

87. परिष्कृत चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, मेरा परिष्कृत चमड़े पर निर्यात शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

88. कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है और हमारे दो तिहाई श्रमिक बल को रोजगार में लगाए हुए है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को सीधे बढ़ावा देने के लिए

मेरा कतिपय मदों पर आयात शुल्क को कम करने का प्रस्ताव है। मेरा प्रमुख मूल कुक्कुट स्टाक पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। कुक्कुट पालन के लिए मिश्रित दाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली कतिपय औषधियों पर शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया जा रहा है। मत्स्य उद्योग के लिए मेरा कतिपय टीकों, झींगों के मिश्रित खाद्य पदार्थों तथा झींगा प्रसंस्करण तैयार करने के लिए आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को भी सामान्य भगीनगी तथा संघटकों पर आयात शुल्कों में सामान्य कटौती करके बढ़ावा दिया जाएगा। तथापि मैंने माल्ट और स्टार्च पर आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने, रेशम के कोकून पर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत और ओलियोपाइन रेजिन पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है ताकि इन क्षेत्रों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

89. मैं भारत आने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क सामान रक्ता 4000/- रुपये से बढ़ाकर 6000/- रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस सीमा के बाद, मौजूदा शुल्क दर 100 प्रतिशत है जिसे मैं घटाकर 80 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इससे विदेशों में काम करने वाले हमारे लोगों को तथा सामान्य तौर पर यात्रियों को सुखद राहत मिलेगी। इस समय, बाहक के माध्यम से वस्तुओं के आयात पर 10,000/- रुपये तक के सामान पर 100 प्रतिशत की दर से तथा इस राशि से अधिक मूल्य के सामान पर 200 प्रतिशत की दर से आयात शुल्क लगता है। उद्योग क्षेत्र की तरफ से काफी लम्बे समय से यह मांग रही है कि बाहक के माध्यम से आयातित माल पर, आयात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए उचित दर पर प्रभार लगाया जाना चाहिए। मैं इसके लिए वित्त विधेयक में प्रावधान कर रहा हूँ। इस संबंध में कानून बनाए जाने तक मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि बाहक के माध्यम से आयातित माल पर बिना किसी मूल्य सीमा के 80 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा।

90. अब मैं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रस्तावों की तरफ आता हूँ।

91. अपने पूर्ववर्ती बजटों में, मैंने सामान्य उपयोग की बहुत सी वस्तुओं जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, दूध से बने उत्पाद, जैम, जेली, मक्खन, पनीर, चाय और काफी पर से उत्पाद शुल्क से छूट दे दी थी। बड़े पैमाने पर उपभोग में लाई जाने वाली अन्य बहुत सी वस्तुओं जैसे खाना बनाने का तेल, वाइसाइकिल और उनके टायरों, किरोमीन स्टोव, ग्रैंड, मसालों और घरेलू बर्तनों को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है। इस बजट में दिए गए मेरे प्रस्तावों से व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क के भार में और कमी आएगी।

92. बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाने वाली बहुत सी वस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। कृषि और कृषि संसाधन में भी प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ रहा है। इसकी मूल सामग्री पर शुल्क की वर्तमान दर 30 प्रतिशत है। मैं प्लास्टिक पर शुल्क की दर को घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्लास्टिक से बनी शुल्क-योग्य वस्तुओं पर भी, मैं उत्पाद शुल्क घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, प्लास्टिक की वे वस्तुएं जो इस समय शुल्क से मुक्त हैं, उन पर यह छूट जारी रहेगी। इन उपायों के साथ-साथ थोक में आयात किए जाने वाले प्लास्टिक पर 45 से 65 प्रतिशत के बीच लगनेवाली मौजूदा आयात शुल्क की दरों को कम करके 40 प्रतिशत की एक समान दर पर निर्धारित किया जा रहा है।

93. इस समय एल्यूमिनियम के अतिरिक्त सभी धातुओं पर 15 प्रतिशत की एक समान दर से उत्पाद शुल्क लगता है। अब मैं, एल्यूमीनियम पर भी उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

94. वर्गीकरण संबंधी विवादों को समाप्त करने तथा शुल्क संबंधी संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए, मैं पूंजीगत वस्तुओं के कच्चे-पूजों पर उत्पाद शुल्क, जिसकी मौजूदा दरें 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत के बीच अलग अलग हैं, को 15 प्रतिशत की एक समान दर पर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे ऐसे विवाद समाप्त हो जाएंगे कि क्या किसी विशेष मव को धातु की वस्तु माना जाए अथवा किसी मशीन का हिस्सा पुर्जा।

95. मैं, श्रम प्रधान फूंकनी प्रक्रिया से तैयार किए जाने वाले शीशे की वस्तुओं, जिन पर इस समय 20 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है, पर भी उत्पाद शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत की रियायती दर करने का प्रस्ताव करता हूँ।

96. बहुत से माननीय संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि उद्योग के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जो दोनों प्रकार से अत्यधिक श्रमिक बहुलता वाले हैं तथा असंगठित क्षेत्र में हैं और वे उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट पाने के हकदार हैं। इन सभी अनुरोधों का सम्मान करते हुए मैं निम्नलिखित वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ :—

— एच डी पी ई और पोलिप्रोपीलीन मोनोकिनामेंट जिसका प्रयोग मुख्यतः मछली पकड़ने वाले जाल और मछलरदानियां बनाने के लिए किया जाता है ;

— विद्युत की सहायता के बिना तैयार किए गए धातु के फटेनर ;

— सूत से बने बिना इलास्टिक तथा दारौक बुनाई वाले कपड़े ;

— बिना ग्राउ वाली सर्जिकल बेंडेज ; तथा

— विद्युत की सहायता के बिना तैयार किए गए तिरपाय के वस्त्र।

97. उच्च सीमा वाली शुल्क दरों को घटाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, मैं निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क की दरों को कम करने का प्रस्ताव करता हूँ :—

— वाजित जल पर 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत

— वातानुकूलन मशीनरी पर 60 प्रतिशत से 40 प्रतिशत

— प्रसाधन सामग्री पर 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत

— चमकोली टाइलों पर 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत

— मुगंधित एंटी-सेप्टिक क्रीम पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

98. मैं सामान्य उपभोग के कुछ क्षेत्रों में भी उत्पाद-शुल्क को कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

— पॉलिमर पेंट पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

— कोको और कोको से बनी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

— माइट से बनी ग्रास वस्तुओं पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

— एस्बेस्टोस रेशों पर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत

— एस्बेस्टोस सीमेंट की वस्तुओं पर 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत

— आडियो और रेडियो मेग्नेटिक टेपों पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

— ड्राई सैल बेट्रीज पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

— कोटेड फैब्रिक्स पर 35 प्रतिशत से 25 प्रतिशत

— सेरामिक लेबोरेट्री वेयर पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

— पटाखों पर 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत

— मोटर वाहनों तथा दूपहियों के पुर्जों पर 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत

— ग्लाम कंटेनर्स पर 30 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

99. मैं पॉलिएस्टर किनामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को 69 प्रतिशत से घटाकर 57.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह दर अभी भी ऊंची है लेकिन राजस्व संबंधी बाध्यताओं के कारण इसमें अभी और कमी करना संभव नहीं है। आयात शुल्कों में समवर्ती कटौती, जिसके बारे में पहले

संकेत दिया गया था, से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि उत्पाद शुल्क में की गई कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

100. बुनाई वाले पोलिएस्टर धागा उद्योग ने अपने उद्योग में मूल्य वर्धन पर 69 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के भार के बारे में शिकायत की है। मैं बुनाई वाले धागे के टैरिफ मूल्य में उपयुक्त समायोजन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ ताकि बुनाई वाले चरण पर ही कुल शुल्क भार को 10.35 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 4.60 रुपए प्रति किलोग्राम किया जा सके। सिलाई धागे पर, जिस पर इस समय उत्पाद शुल्क की दर 23 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक है, मैं 23 प्रतिशत की दर से एक समान उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

101. मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं जो कि अपबंधन-रोधी उपायों के रूप में हैं। मैं "क्ल टाप्स" पर 10 प्रतिशत का उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ कि ताकि ऊनी धागा बनाने के स्तर पर उत्पाद-शुल्क के अपबंधन को रोका जा सके। चूंकि मोडवाट ऋण सुविधा उपलब्ध रहेगी इसलिए यह कर उन्हीं लोगों को चुकाना होगा जो यार्न स्तर पर उत्पाद शुल्क का अपबंधन करने हैं। मैं वस्त्रों और धागों के अवशेषों और कतरनों पर 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी कर रहा हूँ ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र और धागे को अपशिष्ट के रूप में पारित (क्लीयर) करवा लेने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जा सके। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अधिकांशतः सिंथेटिक अवशेष से बनने वाले धागे पर शुल्क की वही दर लागेगी जो कि स्टेपल फाइबर से बनने वाले धागे पर लगती है।

102. विद्युत्-रोधी तारों और केबलों पर 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है। चूंकि इन का घरेलू और उद्योगों में व्यापक प्रयोग होता है, इसलिए मैं इस शुल्क को कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

103. प्लास्टिक की बुनाई वाली थैलियों के विनिर्माताओं की तरफ से लगातार यह मांग रही है कि ऐसी थैलियों का प्रयोग करने वालों को मोडवाट की सुविधा प्रदान की जाए। अब मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूँ कि ऐसी प्लास्टिक की थैलियों के साथ-साथ पटसन की थैलियों का प्रयोग करने वालों की ऐसी थैलियों पर अदा किए गए शुल्क पर पूरा मोडवाट क्रेडिट दिया जाए। ऐसी थैलियों का प्रयोग करने वाले मुख्य उपभोक्ताओं में से सीमेंट उद्योग एक है। इसके साथ ही मैं एकीकृत सीमेंट कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क में मामूली वृद्धि करके 330 रुपए से बढ़कर 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा छोटे सीमेंट कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क को 185 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। खड़ी शापट 622 GI/95—3.

भट्टियों का प्रयोग करने वाले छोटे सीमेंट संयंत्रों के लिए, दैनिक निकासी की सीमा को भी 200 से बढ़ाकर 300 मीट्रिक टन प्रति दिन किया जा रहा है।

104. चाइना और चीनी मिट्टी के बर्तनों की कुछ मदों पर 30 प्रतिशत का शुल्क लगता है जो कि इस उत्पाद के बढ़ते हुए सामान्य प्रयोग को देखते हुए अधिक प्रतीत होता है। उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से, मैं इस शुल्क को कम करके 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

105. लघु एकक देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल, केवल वे ही इकाइयां जिनका पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन 2 करोड़ रुपए से अधिक का न हुआ हो, सामान्य लघु उद्योग छूट स्कीम के अंतर्गत उत्पाद-शुल्क की रियायती दरों के पात्र हैं। मुझे अभ्यावेदन मिले हैं कि 2 करोड़ रुपए की यह वर्तमान सीमा बहुत कम है और इससे भावी विकास हतोत्साहित होता है। इसलिए मैं लघु प्रयोग छूट स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

106. छूट प्राप्त माल के विनिर्माताओं की एक चिरस्थायी समस्या रही है क्योंकि उन्हें विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित अपशिष्ट और कतरनों पर उत्पाद-शुल्क अदा करना पड़ सकता है। इन इकाइयों को केवल ऐसे अपशिष्ट और कतरन पर शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए उत्पाद-शुल्क नियंत्रण के अधीन लाना बहुत तर्कसंगत नहीं होता। इस प्रकार मैं उन अपशिष्टों और कतरनों, जो छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में उत्पन्न होते हैं, को पूर्ण रूप से छूट देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। इससे लघु उद्योग क्षेत्र में बहुत सारी इकाइयों को सहायता मिलनी चाहिए।

107. मैं वर्गीकरण सूचियां फाइल करने की प्रणाली को भी समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। पहली मई, 1995 से विनिर्माताओं को फैक्टरी से माल निकालने के पूर्व कोई वर्गीकरण सूची फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

108. व्यापार और उद्योगों से मोडवाट स्कीम के उदारीकरण और सरलीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं मोडवाट नियमों में निम्नलिखित छूट देने का प्रस्ताव कर रहा हूँ:—

— विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अनुसंधान और विकास उपस्करों के लिए मोडवाट ऋण की अनुमति देना;

— मोडवाट स्कीम के अंतर्गत अधिमूचित किमी भी माल पर शुल्क के भुगतान के लिए मोडवाट ऋण का उपयोग;

— उत्पाद-शुल्क योग्य भाल का विनिर्माण कर रही फैक्टरी विद्युत् उत्पादन के लिए प्रयुक्त भट्ठी तेल और कम गंधक वाले भारी स्टॉक के लिए मोडवॉट ऋण की अनुमति देना ।

109. मैं मध्यवर्ती टायर रज्जु वस्त्र पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगा कर टायरों में प्रयोग होने वाले टायर यार्न के लिए मोडवॉट का विस्तार करने का भी प्रस्ताव कर रहा हूँ । राजस्व हानि की पूर्ति करने के लिए, टायरों पर शुल्क की विशिष्ट दरें लगभग 8 प्रतिशत बढ़ाई जा रही हैं । तथापि दुपहिए और निपहिए वाहनों के टायरों पर उत्पाद-शुल्क में वृद्धि नहीं की जा रही है ।

110. मैं औद्योगिक वस्त्रों पर मोडवॉट स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ । ऊनी वस्त्रों के मामले में भी, मैं मोडवॉट का पूरी तरह विस्तार करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे वस्त्रों पर पहले से ही बुनियादी उत्पाद शुल्क लगता है और इन्हें सीमित मोडवॉट सुविधाएं प्राप्त होती हैं ।

111. मैं मोटे तौर पर सुव्यवस्थित नामावली प्रणाली के आधार पर वस्त्रों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव कर रहा हूँ । यह वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने में सहायक होगा ।

112. मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप, मैं सिगरेटों पर शुल्क की मौजूदा विशिष्ट दरों में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव कर रहा हूँ ।

113. मैंने सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम और उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क टैरिफों में परिवर्तन करने हुए वित्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया है । इनमें सुव्यवस्थित वस्तु विवरण और कूटबंधन प्रणाली, जिसे सुव्यवस्थित प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुसार हमारे देश द्वारा अपनाया गया है, में संशोधनों के आधार पर सीमा शुल्क में कतिपय परिणामी संशोधन शामिल हैं । ये संशोधन मात्र योग्य बनाने वाले उपबंध हैं और इनमें महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी अर्थापत्ति नहीं है । सदन का समय बचाने के लिए मेरा उन्हें दोहराने का प्रस्ताव नहीं है ।

114. उत्पाद शुल्कों में वृद्धि से 335 करोड़ रुपए का राजस्व अभिलाभ प्राप्त होना अनुमानित है जबकि पूरे वर्ष में राहतों की राशि 646 करोड़ रुपए होगी । 311 करोड़ रुपए की कुल निवल हानि में से, केन्द्र को 203 करोड़ रुपए और राज्यों को 108 करोड़ रुपए की हानि होगी । सीमा शुल्क के प्रस्तावों के परिणामस्वरूप 1179 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी । अनुमान लगाने की पारम्परिक विधियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित परिवर्तनों से आयकर में लगभग 900 करोड़ रुपए का राजस्व हानि

होने का अनुमान है, जिसमें से राज्यों को लगभग 700 करोड़ रुपये की हानि होगी । इस प्रकार, केन्द्र की कुल निवल हानि 1582 करोड़ रुपये होगी ।

115. इन विधियों के अंतर्गत सरलीकरण, युक्तिकरण और सुधरे हुए कर अनुपालन से प्राप्त अभिलाभों को पर्याप्त रूप से हिसाब में नहीं लिया गया है । पिछले वर्ष ऐसा लगता था कि पारंपरिक अनुमानों के आधार पर राजस्व प्रस्तावों से होने वाली निवल हानि 4000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी । तथापि मैंने घोषणा की थी कि अनुपालन और बेहतर प्रशासन से होने वाले अभिलाभों के कारण हमारी राजस्व प्राप्तियों को कोई हानि नहीं होगी । यह आशावादिता वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमानों में यथा प्रवर्णित निष्पादन द्वारा पूर्णतः उचित सिद्ध हुई है । बजट में मैंने जिन पर संबंधी परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है वे अनिवार्यतः पिछले वर्ष में किए गए प्रयासों को जारी रखे रहना है और मुझे विश्वास है कि सुधार से होने वाले अभिलाभ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई राजस्व हानि नहीं होगी । इसलिए, मैं अपने बजट प्रस्तावों से किसी राजस्व हानि का अनुमान नहीं कर रहा हूँ । इसलिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा ।

116. सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने वाली अधिमूचनाओं की प्रतिलिपियां यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी ।

117. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने प्रथम बजट भाषण में कहा था कि दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसे विचार को नहीं रोक सकती, जिसे सार्थक बनाने का समय आ गया है । मैंने यह भी कहा था कि मुख्य आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का आविर्भाव ऐसा ही एक विचार था । भारत के पुनरुत्थान की इसी परिकल्पना ने हमारी आर्थिक नीतियों को प्रेरित किया था, जिसके माध्यम से एशिया में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उचित स्थान दिलाया जा सका । हमारी सरकार ने इस परिकल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है और मैं समझता हूँ कि यह सदन मुझसे सहमत होगा कि हमारे प्रयासों को काफी सफलता मिली है । हमने क्रियात्मक कार्यक्रम के माध्यम से विकास के लिए हमारी जनता की सामूहिक इच्छा को जुटाना चाहा है, जो हमें उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय के दोहरे लक्ष्य के प्रति ध्यानबद्ध करता है । लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध मुक्त समाज के ढांचे में व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए भारत जैसे आकार और विविधता वाले देश की तरह विश्व में और कोई उदाहरण नहीं है । इसलिए भारत का अनुभव अत्यधिक विश्वव्यापी महत्व रखता है और विश्व निश्चित रूप से हमारी ओर दिलचस्पी और आशाभरी नजरों से देख रहा है ।

118. जैसा मैं देखता हूँ, भारत अभूतपूर्व अवसरों के द्वार पर खड़ा है बशर्ते कि हमारे पास उनका लाभ उठाने की बुद्धिमानी हो। हमने एक अच्छी शुरुआत की है परंतु अभी भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। हमें अपने प्रयासों में दृढ़ रहना होगा। इसके लिए कठोर परिश्रम और त्याग करने तथा समाज के सभी वर्गों के लिए स्व-अनुशासन की भावना पैदा करने की आवश्यकता होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्पादकता में चौतरफा वृद्धि होने से हमारी जनता के लिए अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर एक वास्तविकता बन सकता है। स्पष्टतया इसका कोई सुगम मार्ग नहीं है। हम आसानी से समृद्धि का मार्ग तय नहीं कर सकते। हम जो राजनीति में हैं, उनका एक विशेष उत्तरदायित्व है। राष्ट्र-निर्माण के मूलभूत कार्य से लोगों का ध्यान हटाने के लिए प्रतिस्पर्धी राजनीति का अनुसरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस देश में राजनीति को आवश्यकता और आत्म-बलिदान की उस भावना को पुनःग्रहण करना चाहिए, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी और उसे सामाजिक परिवर्तन का एक उद्देश्यपूर्ण साधन बनना चाहिए। अब विश्राम करने अथवा अपनी ऊर्जा को अलगाववादी कार्यों में नष्ट करने का समय नहीं है। यह समय हमारे उस सामूहिक संकल्प के प्रति पुनःनिष्ठा धराने और पुनः समर्थन करने का है, जिसके अंतर्गत हमें अपने गणतंत्र के मूल निर्माताओं के सपनों के अनुरूप एक नए भारत के निर्माण के लिए अतृप्त कार्य करना है। यह एक ऐसा भारत होगा, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियाँ प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान भरा जीवन व्यतीत कर सकेंगी और भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करेंगी तथा 21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना कर सकेंगी।

119. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

एन. पी. बागची, अपर सचिव, (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Budget Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1995

F. No. 15(38)B-(D)/94 :—The following is published for general information :—

BUDGET 1995-96

Speech of Shri Manmohan Singh, Minister of Finance
15th March, 1995

PART A

Sir,

I rise to present the Budget for 1995-96.

2. Four years have passed since our Government, under the leadership of Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao, took office in the midst of an unprecedented economic crisis. Our immediate task was to save the nation from a relentless slide

into the abyss of falling production, soaring inflation and deepening poverty. We dealt swiftly with the immediate crisis and we also worked towards a broader objective of shifting the economy on to a path of rapid, employment-generating growth. Our aim was to raise India to her rightful place in the comity of nations.

Sometimes, in the heat of political debate, we lose sight of what has already been achieved. Let me take a few minutes to outline how far we have come since those grim days of 1991 :

- " The growth of our economy had fallen to less than one per cent in 1991-92. We brought the economy back to a growth of 4.3 per cent per year in the two years thereafter, and growth has accelerated further to 5.3 per cent in 1994-95. Few countries can claim as quick and smooth a recovery from as deep an economic crisis.
- " Industrial growth had collapsed to about half of one per cent in 1991-92. Today, Indian industry is experiencing a vibrant, broad-based recovery with industrial growth of 8.7 per cent in April-November, 1994. The manufacturing sector is growing even faster at 9.2 per cent and the capital goods sector is growing at 24.7 per cent. I hope that those critics who predicted that our industrial and trade reforms would hurt Indian industry will look at the reality and think again.
- " There are signs of a strong revival in domestic industrial investment in 1994-95 as Indian industry modernises and upgrades technology, and improves competitiveness. Foreign direct investment is also responding well to the new policies, with large investments flowing into key infrastructure sectors such as Power and Telecommunications.
- " Foodgrain production had fallen to 168 million tonnes in 1991-92. This year, it will be an all-time record of 185 million tonnes. Our farmers have clearly benefited from the policy of offering remunerative prices and have returned a strong production performance.
- " Public stocks of foodgrain, which provide an invaluable insurance against bad weather and other contingencies, had declined to 14.7 million tonnes three years ago. They have been rebuilt to a record level of 31 million tonnes, as on January 1, 1995.
- " Growth has created new jobs for our people. In 1991-92, total employment grew by only about 3 million. In each of the two years thereafter, employment increased twice as fast, with about 6 million new jobs added each year. The increase is expected to be even higher in 1994-95. The drawing room Cassandras, who predicted massive unemployment as a consequence of the reforms, have been conclusively proved wrong.
- " The inability to manage our external payments was the immediate cause of our collapse in 1991. I am sure, Honourable Members are aware of the remarkable change that has taken place in this area. The dollar value of exports fell by 1.5 per cent in 1991-92. In 1994-95 our exports have grown by over 17 per cent in the first 10 months. This follows a 20 per cent increase in 1993-94. Imports have also grown in line with the revival of the economy but the balance of payments situation is comfortable.
- " The fears that were voiced in some quarters that our trade policy would generate a disruptive flood of imports and weaken the economy have been shown to be completely unfounded. Liberalisation and openness have actually increased our self-reliance. Exports now finance over 90 per cent of imports, compared to only about 60 per cent in the latter half of the eighties. The external deficit on current account was over 3 per cent of GDP in 1990-91. It is expected to be less than 1/2 per cent in 1994-95.

* At the time of the crisis, our external debt was rising at the rate of 8 billion dollars a year. In 1993-94, the increase in external debt was reduced to less than one billion dollars. In the first half of 1994-95, our external debt stock actually declined by almost 300 million dollars.

* Our foreign currency reserves had fallen to barely one billion dollars in June 1991. On March 10, 1995 they stood at over 20 billion dollars.

* A key element of our strategy was to give top priority to strengthening anti-poverty programmes, once the initial crisis was overcome. We have fulfilled this promise. Plan expenditure on employment and anti-poverty programmes in the Central Sector has been increased very sharply in the last two budgets. The allocation for Rural Development has been more than doubled from Rs. 3100 crores in 1992-93 (BE) to over Rs. 7000 crore in 1994-95 (BE). Over the same period the allocation for Elementary Education was increased by 84 per cent, for Adult Education by 78 per cent and for Health by 91 per cent.

4. These indicators testify to a remarkable turnaround, in a relatively short time. We inherited an economy near collapse four years ago. We have transformed it into an economy showing strong growth in agricultural and industrial output, a strong revival of domestic investment, a steady increase in foreign direct investment, renewed growth of employment and a comfortable foreign exchange position. This is the result of the hard work of our farmers and industrial workers, our managers and exporters, combined with the far sighted economic policies implemented by the government under the leadership of Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao. What is most encouraging is the emergence of a broad national consensus in support of reforms, a consensus which vindicates our strategy of moving forward steadily and surely on the path of reform.

5. We have come a long way, but the journey is far from over. We need to redouble our efforts in several areas to consolidate our gains, and push the economy to even better performance. This is both feasible and also necessary to achieve our goals. Reforms in the areas of taxation, trade and industrial policies and the financial sector have yielded good results. They need to be completed as planned, so as to enhance the efficiency and competitiveness of our economy. Barriers to further expansion of agriculture have to be identified and lifted. The public sector has to be revamped. Industrial relations have to provide for greater flexibility in deployment of labour. Delivery systems for social services have to be modernised, plugging loopholes and promoting cost effectiveness. Capital market reforms have to be widened and deepened to strengthen investor protection. Insurance sector reforms have to be pursued with the aim of greatly widening access to insurance services and promoting competitive and efficient customer-oriented services. We must and will push ahead in all these areas.

6. There are also some weak spots, which have surfaced and need to be addressed urgently. After the initial successes in fiscal consolidation, further progress has proved much more difficult. The fiscal deficit increased sharply in 1993-94 and the pressure on the deficit has continued in 1994-95. These developments must be countered through determined action. If we try to fund every project and programme irrespective of revenues available, we only generate high inflation, high interest rates which choke off investment, and a proliferation of under-funded, incomplete projects. This approach will only jeopardise our basic objective of development with social justice since it is the poor who will suffer most from the resultant inflation and slow growth of employment opportunities. We must, therefore, ensure that fiscal discipline is further improved in the years ahead.

7. Inflation has surfaced again as a serious problem. We had succeeded in lowering the rate of inflation from the peak of 17 per cent in 1991 to around 7 per cent in the middle of 1993, but since then inflation has accelerated again and currently exceeds 11 per cent. This acceleration has occurred because of several factors. One reason is the sharp increase in procurement prices in the previous three years. Another factor is the shortfall in production in critical sectors such

as sugar, cotton and oilseeds. The persistence of fiscal deficits at levels higher than they should be, has also contributed to inflationary pressure. Recognizing these problems, we will tackle inflation on a priority basis in the year ahead.

8. Monetary policy has already been tightened to reduce the growth of money supply. Interest rates on bank deposits have been raised to give greater encouragement to savings. Taking advantage of the improved foreign exchange position, imports of key essential commodities, such as sugar, cotton, pulses and edible oils have been freely allowed with zero or low duties to moderate inflationary pressure. We are also taking advantage of the comfortable foodgrain stocks to undertake continuous open market sales of wheat and rice with a view to moderating price pressure in these items. The Public Distribution System (PDS) has been strengthened and supplies through the PDS are being supplemented by necessary imports of sugar and edible oils. Over the coming year, we will use all instruments available to ensure stability in prices of wheat, rice and edible oils. Tariff and trade policies will be deployed to ensure that domestic prices of industrial products do not rise unduly. The consumer movement will be strengthened and Government will be vigilant in curbing restrictive practices and hoarding. My revenue proposals, to which I will come a little later, are also designed to check inflation in commodities of mass consumption.

9. Infrastructure is another area of potential weakness. If we are to aim at economic growth of 7 to 8 per cent, which has been achieved in other countries and which alone can provide the jobs we need for our growing labour force, then we need much larger investment and much greater efficiency in key infrastructure sectors such as power, roads, ports, irrigation, railways and telecommunications. Sound financial management holds the key to progress in this area. Adequate supply of quality infrastructure depends crucially on the financial viability of these sectors, which in turn depends upon the adoption of reasonable cost recovery policies. To take the example of power, many State Governments are unable to finance new investment in power generation because of the financial weakness of the State Electricity Boards. Taking advantage of the Central Government's initiative to encourage private investment in power generation, many State Governments are actively trying to attract private sector investments into this area. But private sector investors are unwilling to invest in Power unless the State Governments and the Central Government provide guarantees and counter-guarantees to reassure the private sector producers that they will be paid for the power they generate. Such counter-guarantees are justifiable only if they are viewed as providing temporary breathing space, during which State Electricity Boards undertake necessary reforms of their institutional structure, operating practices and pricing policies. In the long run, we cannot escape the reality that the users of electricity must pay for its cost. The same criterion holds for other infrastructure sectors also. Once financial viability is assured, we can expect a renewed surge of both public sector and private sector investments in these areas.

10. I shall now deal with some issues of social equity and poverty alleviation. In my first Budget speech itself, I had emphasised that economic growth and restructuring are not ends in themselves. They are only the means to improving the lives of ordinary citizens. I wish to assure the House that this concern has been central to our strategy from the very beginning. Experience in our own country, as also from all over the world, shows that the surest antidote to poverty is rapid and broad based growth. This is precisely what our economic reforms seek to achieve. We also recognise that the fruits of growth will take time to reach some of the poorest and weakest sections of our society. To ensure that they too derive benefit in the short run, we have given the highest priority to strengthening programmes of rural development, employment generation, primary education, primary health and other key social sector programmes. These programmes, coupled with accelerating economic growth over the last three years, are beginning to have desirable effects on employment and poverty. I have already mentioned that total employment is expanding much faster than three years ago. Real wages of agricultural labourers had declined in 1991-92 during the crisis. They had increased above pre-crisis levels by 1993-94. Available information on vital statistics, like the crude death rate and the infant mortality rate, also indicates a clear recovery in general living standards after 1991-92.

11. The message is clear : the task of lifting the age-old burden of poverty in our society is daunting, but we are on the right track. We must persevere with our two-track strategy of accelerating growth, investment and modernisation on the one track, and strengthening anti-poverty programmes on the other. The Central Plan allocations and the tax proposals in this Budget are designed to advance both elements of this strategy. Before coming to these proposals, I would like to outline some new initiatives aimed at strengthening the income-earning opportunities for the weaker segments of our society.

12. Inadequacy of public investment in agriculture is today a matter of general concern. This is an area which is the responsibility of the States, but many States have neglected investment in infrastructure for agriculture. There are many rural infrastructure projects, which have been started but are lying incomplete for want of resources. They represent a major loss of potential income and employment to the rural population. To encourage quicker completion of projects in rural infrastructure, I propose to establish a new Rural Infrastructural Development Fund within the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) from April 1995. The Fund will provide loans to State Governments and State owned Corporations for completing ongoing projects relating to medium and minor irrigation, soil conservation, watershed management and other forms of rural infrastructure. The loans will be on a project-specific basis with repayment and interest guaranteed by the concerned State Government. Priority will be assigned to projects which can be completed within the least time period. Resources for the Fund will come from commercial banks which will be required by Reserve Bank of India (RBI) to contribute an amount equivalent to a bank's shortfall in achieving the priority sector target for agricultural lending, subject to a maximum of 1.5 per cent of the bank's net credit. This is expected to create a corpus of about Rs. 2,000 crore for completion of rural infrastructure projects.

13. Our Scheduled Castes and Scheduled Tribes citizens are amongst the poorest members of our rural society. In the one hundred predominantly tribal districts, NABARD will open an exclusive line of credit to Cooperatives and Regional Rural Banks for meeting the credit needs of Scheduled Tribes. Rs. 400 crore will be earmarked for this purpose during 1995-96. NABARD will also earmark a further Rs. 100 crore for financing Scheduled Castes and Scheduled Tribes beneficiaries identified by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Corporations. This amount would be available to the commercial and co-operative banks for meeting the investment needs of Scheduled Caste and Scheduled Tribe beneficiaries in both farm and non-farm activities.

14. Khadi and village industries provide crucial non-farm earning opportunities to our rural population. I propose to establish a new scheme under which the banking system will provide Rs. 1,000 crore on a consortium basis to the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), which will lend to viable khadi and village industry units, either directly or through State level Khadi and Village Industries Boards (KVIBs). The Central and State Governments will guarantee these loans by commercial banks to KVIC and KVIBs, respectively.

15. The handloom sector employs millions of poor weavers. At present, NABARD refinancing to this sector is restricted to the flow of credit through the District and State Co-operative Banks. Henceforth, NABARD will extend refinancing to commercial banks also for extending credit to co-operative handloom institutions. Steps are also being taken to accelerate the flow of credit to the Handloom Centres and Quality Dyeing Units coming under the scheme initiated last year.

16. Our Small Scale Industries employ 14 million workers and account for 40 per cent of our total manufacturing output and 35 per cent of our exports. This dynamic sector must be strengthened and assisted to better serve the goals of growth, employment generation and self-reliance through exports. A Technology Development and Modernization Fund will be established in the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) to provide financial assistance to quality projects aimed at strengthening the export capability of small scale industries. The initial amount earmarked for this Fund will be Rs. 200 crore. The financial assistance, which would be directly provided by SIDBI to eligible small scale units, can take the form of either loans or equity.

17. A National Equity Fund Scheme was established in 1987, to provide equity assistance to tiny small scale units with projects of less than Rs. 10 lakhs and located in places with a population not exceeding 5 lakhs (1.5 lakhs in the case of Hill Areas and the North Eastern Region). I propose to extend the National Equity Fund Scheme to all tiny small scale units irrespective of their location, except for units in metropolitan areas. Furthermore, the scope of this scheme will be enlarged to cover expansion, modernization, technology upgradation and diversification. The scheme, which is managed by SIDBI, will continue to be funded by the Central Government and SIDBI on 50:50 basis.

18. Adequate availability of credit from the banking system is critical for the small scale sector. The Government, in consultation with banks, has formulated a Seven Point Action Plan for improving the flow of credit to this sector. A key feature of the Plan is the setting up of specialized bank branches to serve the needs of small scale units in 85 identified districts, each with more than 2,000 registered small scale units. The public sector banks will ensure that 100 such dedicated branches are operational before the end of 1995-96.

19. The North Eastern region of our country merits special attention. With a view to accelerating industrial development, a new North Eastern Development Bank (NEDB) is being established to finance creation, expansion and modernization of industrial enterprises and infrastructure projects in the region. The Bank will be located within the region. It will have an authorized capital of Rs. 500 crore. Initial contributions to capital will be provided by All India Financial Institutions such as IDBI, ICICI and UTI, providing scope for contribution from other investors subsequently.

20. In addition to these measures for enhancing income earning opportunities for the weaker sections of our society, I am pleased to announce four far-reaching programmes for the general welfare of the poor, especially in rural areas. The first programme addresses the serious deficiency in housing facilities for the rural poor. As Honourable Members are aware, there is a major ongoing rural housing programme, the Indira Awas Yojana. About 4 lakh dwelling units are expected to be provided on a subsidized basis in 1994-95 to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and freed bonded labourers. For 1995-96, the housing target is being more than doubled to 10 lakh units. With this initiative, we will be able to build 50 lakh rural dwelling units in the next five years. This will go a long way towards solving the critical shortage for basic shelter among rural poor.

21. The greatest hardships among the poor are often suffered by the old and the weak, most of whom are unemployable. To soften the hardship in their twilight years, a National Social Assistance Scheme has been proposed to cover the poor and needy. One component of the scheme is the provision of a national minimum old age pension of Rs. 75 per month to people above 65 years of age who are below the poverty line. A second component provides lump-sum survivor benefits to poor households, on the death of the primary bread earner, of Rs. 5000. The third component aims at provision of sustenance for pre-natal and post-natal maternity care to women belonging to poor households for the first two births. The scheme will eventually cover about 14 million neediest beneficiaries from households below the poverty line. Three quarters of the beneficiaries are likely to be women needing assistance on account of old age, widowhood and maternity. The Scheme, to be funded jointly by the Centre and the States, will be implemented by the States through Panchayati Raj institutions. For this purpose, I am appointing a Committee to work out the details of this Scheme.

22. The social assistance package will be complemented by a new Group Life Insurance Scheme of the LIC which will be implemented by Panchayats in rural areas. Under this scheme, life cover of Rs. 5000 will be provided for a modest annual premium of around Rs. 70. For poor households, the Central Government will subsidise 25 per cent of the premium with the State Government meeting an equal amount and the beneficiary contributing 50 per cent. The subsidy will be limited to one policy per poor household. For the others, there will be no subsidy on the premium. The object of the scheme is a massive promotion of social insurance and thrift in rural areas with the active involvement of Panchayats.

For poor households, it will provide a second tier of partly subsidised security supplementing the survivor benefit and will also inculcate the habit of saving. The LIC will be working out the details of the scheme.

23. Schemes to provide mid-day meals for school children have a beneficial impact not only on child nutrition but also on school attendance. Some of the State Governments have been operating school mid-day meals schemes. As part of the emphasis being laid by this Government on the primary education, and taking into account the comfortable food stocks with the public sector agencies, it is appropriate that the Central Government should be willing to participate in phased expansion of these schemes. The modality of implementing this, with necessary local variations, will be worked out by a Committee to make it operational in 1995-96.

24. Taken as a whole, these new initiatives for funding agricultural infrastructure, promoting handlooms and Khadi and Village industries, expanding rural housing and introducing social insurance will greatly strengthen the anti-poverty component of our strategy. In parallel, we will also continue with the economic reforms, which have already yielded excellent results.

25. The industrial, trade and tax reforms, which have created demonstrable buoyancy in industrial production, investment and exports, will be continued, with a special effort to improve implementation at the ground level. An important positive development is the upsurge of investment proposals in infrastructure sectors, such as power and telecommunications. We will ensure that the flow of investment into these critical sectors is expedited. Reforms in the capital markets are being pursued vigorously. Major amendments have been made recently in the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act to give SEBI powers for effective regulation of the capital markets. We propose to introduce legislation to set up Central Depositories later this year. We will continue our efforts at financial sector reforms.

26. In my speech last year, I had drawn attention to the report of the Committee on Reforms in the Insurance Sector and indicated that we would evolve a broad consensus on the future direction of reforms. As first step, I propose to establish an independent Regulatory Authority for the Insurance industry. Necessary legislation will be introduced shortly.

27. I shall now briefly go over the Revised Estimates for 1994-95.

28. The Budget Estimates for 1994-95 had placed the total expenditure at Rs. 1,51,699 crore. This is now expected to go up to Rs. 1,62,272 crore, an increase of Rs. 10,573 crore.

29. Budget Estimates for the current year provided Rs. 46,582 crore as budget support for Plan expenditure. This is being enhanced to Rs. 48,761 crore to accommodate additional assistance to the State Plans and additional allocations for the MPs Local Area Scheme.

30. Non-Plan expenditure in the current year is placed at Rs. 1,13,511 crore which represents an increase of Rs. 8,394 crore over the Budget Estimates. Additional provision has had to be made in the Revised Estimates towards food and fertilizer subsidies. The provision for food subsidy has to be substantially increased by Rs. 1,100 crore because of the time lag in the revision of issue prices of foodgrains. Fertilizer subsidy is being increased by Rs. 1,166 crore from the budgeted level to cover the requirement of imports and to clear past arrears. There has been an unprecedented rise in collections from small savings schemes this year. Consequently, an additional amount of Rs. 4,497 crore is being provided in the Revised Estimates as loans to States and Union Territories.

31. Gross tax revenues were estimated at Rs. 87,136 crore in the Budget Estimates. I am happy to report that our tax reforms are beginning to have the expected impact and gross tax revenues are Rs. 2,695 crore higher than the

Budget Estimates, reaching a figure of Rs. 89,831 crore in the Revised Estimates for 1994-95. This is a vindication of our strategy of tax reform, and also a tribute to the hard work and dedication of the revenue department, without whose unstinting efforts this result could not have been achieved.

32. External loans net of repayment, are placed at Rs. 3,947 crore compared to the Budget Estimates of Rs. 4,279 crore.

33. Though tax collections and other non-debt receipts have been higher than budgeted, the gaps have been outweighed by much larger increases in plan and non-plan expenditure. The fiscal deficit was originally budgeted of Rs. 54,915 crore or 6 per cent of GDP. The fiscal deficit in the Revised Estimates comes to Rs. 61,035 crore which is about 6.7 per cent of GDP. However, nearly three quarters of this deterioration is due to the extraordinary rise in small saving collections, 75 per cent of which are passed on to the States. Thus the bulk of the deterioration in the fiscal deficit is not on account of increased expenditure of the Central Government, but only a reflection of larger small savings as compared to the Budget Estimates, which are on lent to the States. If this element is excluded, the Centre's fiscal deficit would be only 6.2 per cent of GDP compared to the Budget target of 6 per cent.

34. The Tenth Finance Commission (TFC) submitted its Report covering the five year period of 1995-2000, on November 26, 1994. The Report recommends a substantial increase in transfers to the States. Despite the severe constraint on the Centre's resources, the Government has accepted the recommendations of the Commission and these are being implemented with effect from 1995-96. The flow of funds based on Finance Commission devolution and transfers will increase by about 22 per cent, from Rs. 28,832 crore in 1994-95 to Rs. 35,055 crore in 1995-96. We expect the States to use the additional resources for the purposes for which they are released and ensure that the fruits of the schemes reach the intended beneficiaries.

35. I now turn to the Budget Estimates for 1995-96. The total expenditure is estimated at Rs. 1,72,151 crore. The total budgetary support from the Central Government's budget to the Central and the State Plans is being placed at Rs. 48,500 crore in 1995-96, which represents an increase of Rs. 1,918 crore over the level in Budget Estimates 1994-95.

36. The total outlay of the Central Plan 1995-96 has been increased to Rs. 78,849 crore from Rs. 70,141 crore in the Budget Estimates 1994-95. The budgetary support for the Central Plan 1995-96 has been increased to Rs. 28,994 crore from Rs. 27,278 crore in the Budget Estimates 1994-95. The balance will be met by the internal and extra budgetary resources of the Central Public Sector Enterprises to the extent of 63 per cent, as against 61 per cent in Budget Estimates 1994-95.

37. I am providing Rs. 19,506 crore as Central Plan assistance to States and Union Territories in the Budget Estimates 1995-96 compared to Rs. 19,304 crore in Budget Estimates 1994-95. It is relevant to note that the plan transfer to States and UTs for 1994-95 include Rs. 2,680 crore as part of the Ninth Finance Commission decisions. Tenth Finance Commission has not suggested any transfer on Plan Account. Thus the discretionary plan transfer by the Centre to States and UT goes up from Rs. 16,624 crore in 1994-95 to Rs. 19,506 crore in 1995-96, yielding an increase of over 17%. This amount has to be viewed in the background of substantial increase in transfer to the State as a result of the recommendations of the Tenth Finance Commission.

38. In line with our strategy of giving priority to programmes which directly benefit the poor, budgetary support to the Central Plan is being concentrated on Rural Development, Employment and Poverty-alleviation programmes and human resource development sectors. As Honourable Members are aware, the directly targeted Rural Development programmes for eradicating rural poverty have received special emphasis and enhanced outlays during the reform

process. In the last budget, the outlay for the Department of Rural Development was raised to Rs. 7,010 crore, more than double the amount of Rs. 3,100 crore budgeted two years earlier in 1992-93. For 1995-96, this allocation is being further increased to Rs. 7,700 crore. With this we will be well on the way to meeting the Eighth Five Year Plan target of Rs. 30,000 crore of Central Plan outlay for Rural Development. It is estimated that the Rural Employment programmes under the Department of Rural Development generated about 800 million mandays of employment in 1991-92. In 1995-96, these programmes are estimated to generate 1290 million mandays of employment.

39. The Annual Plan of 1995-96 will continue to lay stress on improving productivity in the agricultural sector and diversifying the pattern of agriculture into higher value generating farm schemes like horticulture. Revitalising the cooperatives for providing credit inputs and extension support, marketing and processing would be another thrust area. The flow of agricultural credit through cooperatives is projected at Rs. 14,000 crore in 1995-96, as compared to an estimate of about Rs. 12,000 crore in 1994-95. Assistance will be given to 220 cooperative societies for women and 330 cooperative societies for weaker sections. It is expected that over 38,000 hectares would be brought under drip irrigation. Integrated pest management, which is eco-friendly, will be extended and 1500 training-cum-demonstrations will be organised to train over 50,000 farmers. 40,000 hectares are expected to be covered under intensive fish farming.

40. The spread of educational opportunities is essential for social and economic development. Despite severe budgetary constraints, the Plan Outlay for Education in 1995-96 is being increased from Rs. 1,541 crore in 1994-95 to Rs. 1,825 crore in 1995-96. Elementary Education is particularly important, especially for improving the position of girls and women in our society. The outlay for Elementary Education is being increased substantially by 24.5 per cent to Rs. 651 crore. Under Operation Black Board, primary schools with enrolment of more than 100 children are being providing a third teacher. The allocation for Operation Black Board is being increased by 30 per cent for 1995-96. The allocation for post-matric scholarships for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been increased from Rs. 105 crore in 1994-95 to Rs. 145 crore in 1995-96. This will help additional coverage of deserving students. To assist the State Governments, Government of India is passing on all the external assistance received for Primary Education as grants to State Governments, irrespective of the terms on which the assistance is received by the Central Government.

41. The combined Plan Outlay for the Departments of Health and Family Welfare is being increased to Rs. 2,251 crore in 1995-96. The allocation for the National Malaria Eradication Programme for 1995-96 is being increased by 32 per cent to Rs. 139 crore, so that coverage can be extended to 163 million people with top priority being accorded to tribal areas and North Eastern States where the problem of malaria has been endemic. Rs. 80 crore is being allocated in 1995-96 for the Leprosy Control Programme which aims to eliminate transmission of this disease by the year 2000. An allocation of Rs. 726 crore is proposed for Family Welfare Services directly meant for rural areas, including Rs. 160 crore for maintenance of 5435 Rural Family Welfare Centres and Rs. 190 crore for the maintenance of 9577 Rural Sub-Centres.

42. Total non-Plan expenditure in 1995-96 is estimated to be Rs. 1,23,651 crore. The outlay for Defence has been increased to Rs. 25,500 crore, keeping in mind national security imperatives. An amount of Rs. 5,400 crore is being earmarked for fertiliser subsidy in 1995-96. In addition, Rs. 500 crore has been earmarked for cheaper supply of phosphatic and potassium fertilisers to farmers, thus raising the total effective fertiliser subsidy to Rs. 5,900 crore. Food subsidy receives an allocation of Rs. 5,250 crore.

43. Turning to revenue receipts, gross tax revenues at the existing rates of taxation, are estimated at Rs. 1,03,762 crore. The payment of share of taxes to States is placed

at Rs. 29,388 crore. The net revenue receipts to the Centre, including non-tax revenues are estimated to increase from Rs. 86,084 crore in 1994-95, to Rs. 1,00,787 crore in 1995-96.

44. In the area of capital receipts, traditional market borrowings are put at Rs. 3,700 crore. Other medium and long term loans are estimated at Rs. 19,000 crore and short term loans at Rs. 4,387 crore. Net external assistance is estimated at Rs. 4,456 crore. As in previous years, the Government intends to continue the process of disinvestment of the equity of public sector enterprises. The Budget Estimates provide for receipts from disinvestment of Rs. 7,000 crore, a significant increase from the figure of Rs. 5,237 crore in the Revised Estimates for 1994-95.

45. Taking into account other changes in receipts and expenditure, total receipts at existing rates of taxation are estimated at Rs. 1,67,151 crore, while total expenditure is estimated at Rs. 1,72,151 crore. This results in a budget deficit of Rs. 5,000 crore. The fiscal deficit emerging from these estimates for 1995-96 will be Rs. 57,634 crore, which will be about 5.5 per cent of GDP. I would have liked to do better, but on balance I feel that a fiscal deficit of this order can be absorbed, if the existing growth momentum is maintained.

PART B

46. I now turn to my tax proposals for 1995-96.

47. Over the past three years, we have made a number of structural changes in our tax laws covering both direct and indirect taxes. Unlike earlier isolated attempts to modify the tax system, these changes were part of a medium term programme of tax reform guided by certain general principles that have gained wide acceptability. We wanted to build a structure which is simple, relies on moderate tax rates but with a wider base and better enforcement, serves the objectives of equity and provides the incentives and signals consistent with developing an internationally competitive, dynamic economy.

48. Direct taxation is the most equitable form of raising revenues, but our experience in the earlier years of high tax rates showed that high rates did not lead to high collections. I am happy to report that our decision to reduce rates and thereby encourage compliance has yielded good results. Personal income and corporation taxes, taken together, are expected to increase by more than 25 per cent in 1994-95. The share of direct taxes in GDP has increased from 2.1 per cent in 1990-91 to 2.8 per cent in 1994-95.

49. In the area of customs duty our objective was to reduce the high rates of import duty gradually, so as to lower costs of production and improve competitiveness of user industries while allowing domestic producers facing competition from imported goods reasonable time to adjust. The strong growth of Indian industry in 1994-95, to which I have referred earlier, demonstrates conclusively that customs duty reforms have succeeded in imparting the necessary dynamism to industrial production.

50. In the area of excise duties, our objectives were to simplify the structure, broaden the base, reduce high rates of duty which encourage evasion, shift to ad valorem rates as far as possible and extend the coverage of MODVAT. The results are evident in the impressive growth of excise revenues in 1994-95.

51. I am reassured by these results that our basic strategy of tax reforms stands fully vindicated. Together with administrative steps being taken to improve revenue collection, I am now confident that we can create a tax structure which will ensure buoyant revenues while also stimulating growth of production and employment.

52. Mr. Speaker Sir, after this brief overview, I would like to present the details of my proposals relating to direct taxes.

53. I have received many representations from Members of Parliament, trade unions and others requesting for increase in the exemption limit for personal income-tax. Our Government has consistently responded to the genuine needs of the common man. I, therefore, propose to further raise the exemption limit for income tax from Rs. 35,000 at present, to Rs. 40,000.

54. We need to strengthen incentives for savings. At present, under section 80L of the Income-tax Act, income by way of interest and dividend from certain specified financial assets is exempt from income tax to the extent of Rs. 10,000 per annum. In order to provide greater fillip to domestic savings by individuals and HUFs, I propose to raise this limit to Rs. 13,000. This will provide both relief and an added incentive for savers.

55. With these changes, a salaried individual will not pay any tax upto a salary level of Rs. 55,000. In the case of working women, this limit is even higher at Rs. 58,000. In addition, such an individual would benefit from an additional exemption of Rs. 13,000 if he or she takes full advantage of the exemption for income from savings instruments under section 80L. The tax exempt income could therefore reach a maximum of Rs. 68,000 generally and Rs. 71,000 for working women. It is only beyond this level that such individuals will start paying tax and that too only at modest rates.

56. Inadequate infrastructure is a key constraint to our economic progress. In order to promote exemption of quality infrastructure, I propose to allow a five year tax holiday for any enterprise which builds, maintains and operates infrastructure facilities in the area of highways, expressways and new bridges, airports, ports and rapid mass transport systems. This tax holiday will be available to enterprises which commence operation after 1st April, 1995. As an incentive to financial institutions to provide long-term finance for development of such infrastructure, I propose to allow a deduction of upto 40 per cent of their taxable income derived from financing of these investments, provided this amount is credited to a special reserve.

57. Under section 80-IA of the Income-tax Act, new industrial undertakings, hotels and shipping concerns commencing operation before 31st March, 1995 are entitled to a deduction of 30 per cent of their income if they are companies or 25 per cent of their income if they are non-corporate entities. This incentive is available to co-operative societies for the first 12 years, and to others for the first 10 years of operation. As a special measure of support to small scale industries, I propose to extend this concession to them for five more years. Thus, new industrial undertakings in the small scale sector which commence operation before 31st March, 2000 will be eligible for this concession.

58. Exports of software have grown rapidly and represent a potentially dynamic segment of export earnings. Software exporters have, however, represented that the deduction under section 80HHE available to them is extended from year to year whereas section 80HHC for export to goods is open-ended. I propose to accede to their request to place section 80HHE on the same basis as section 80HHC.

59. Venture capital funds can be an important instrument for promoting growth of new firms and technologies which often involve high risk. The tax laws of many countries allow income of such funds to be exempt from taxation in the hands of the fund but tax it, after distribution, in the hands of the shareholders. In order to encourage the formation of venture capital funds on similar lines in India, I propose to exempt from tax, income by way of dividend and long term capital gains from equity investments made by approved venture capital funds or venture capital companies. Such venture capital funds will be required to invest only in unlisted companies engaged in manufacturing. Income will, however, be fully taxable in the hands of the shareholders.

60. On Independence Day, 1994, the Prime Minister had announced the launching of the Integrated Urban Poverty Eradication Programme. Under this programme, the

Ministry of Urban Development is setting up a National Urban Poverty Eradication Fund (NUPEF). I propose to allow 100% deduction from income in respect of contributions made to this fund.

61. Under section 80-U of the Income-tax Act, a separate deduction of Rs. 20,000 is allowed from the total income of handicapped persons. I have received several representations from handicapped persons and welfare organisations stating that these individuals need additional relief on account of increased cost of medicines and living aids. Recognising their needs, I propose to raise the level of deduction for handicapped persons from Rs. 20,000 at present to Rs. 40,000.

62. Many voluntary relief organisations have represented that the parents or guardians of children with severe disability such as spastic children, face great mental agony having to worry about the burden of providing for the maintenance of the disabled after the death of the parents or the guardian. I see merit in this representation. I, therefore, propose to allow a new deduction of upto Rs. 20,000, from the taxable income of parents or guardians of handicapped children provided this amount is deposited in any approved scheme of LIC, UTI etc. for providing recurring or lump sum payment for the maintenance and upkeep of a handicapped dependant after the death of parents or the guardian.

63. A number of funds have been established by trade unions for the welfare of the employees and their dependants. These funds are used to provide cash benefits in the event of superannuation, illness or death or to meet the cost of education of the employees' children. I propose to exempt the income of such funds from income tax.

64. The National Minorities Development and Finance Corporation has been set up in pursuance of the announcement made by the Prime Minister on Independence Day, 1993. The main object of the Corporation is to promote economic and developmental activities for the benefit of the members of the minority communities. I propose to exempt from income tax the income of this corporation as well as of similar corporations established by any State Government. I also propose to allow deduction in respect of donations made to these corporations, under section 80G of the Income-tax Act.

65. Upgradations of human resources is a high priority. The fundamental need is for improvement of primary and adult education in rural and semi-urban areas where facilities for such education are deficient. In addition to public funding, we have to encourage private contributions for this purpose. In 1993, I had extended the benefit of 100% deduction from taxable income for donations to universities and educational institutions of national eminence. This year, I propose to extend 100% deduction for donations to Zila Saksharta Samitis constituted in the districts for the promotion of elementary education. This measure will help to mobilise additional resources for elementary and adult education in rural and semi-urban areas and enable us to intensify our total literacy campaign.

66. All over the world, revenue administrations widen the tax base by enlarging the scope of deduction of tax at source. This brings in more persons into the tax net and assists the transition to lower rates of taxation. It also helps in the reporting of correct incomes. In many countries, income from professional and technical services is subject to deduction of tax at source. In order to prevent under-reporting of income in this sector, I propose to introduce a new provision in the Income-tax Act subjecting the sums payable by way of fees for professional or technical services to the requirement of deduction of income-tax at source at the rate of 10 per cent. There will be no deduction of tax at source where the aggregate of payments or credits during the financial year is below Rs. 20,000 or where payments are made by individuals and HUFs.

67. Tax is deducted at source on payments made in excess of Rs. 10,000, to contractors under section 194C of the Income-tax Act. Legal disputes have been arisen whether the TDS provisions will apply to transport contracts, advertisement contracts, broadcasting contracts, telecasting contracts and catering contracts. To avoid further litigation and check

tax avoidance, I propose to provide for deduction of tax at source in these cases at the existing rate of 2 per cent for the main contract and 1 per cent for sub-contracts. Taking into account the inflation over the years, I also propose to raise the limit below which deduction at source is not necessary from Rs. 10,000 at present to Rs. 20,000.

68. The income from units of mutual funds or of the Unit Trust of India, though liable to income-tax, is not subject to deduction of tax at source in most cases. This has led to non-reporting or under-reporting of such income. In order to prevent misuse and ensure a uniformity of treatment with other financial instruments I propose to provide for deduction of tax at source from such incomes at the rate of 20 per cent in the case of companies and at the rate of 15 per cent for all others including individuals and HUFs. There will be no change in the present tax treatment of non-residents or offshore funds. In the case of resident unit-holders, deduction of tax at source will be made only if the aggregate amount of income payable under each scheme during a financial year exceeds Rs. 10,000. No deduction of tax at source will be required where units have been issued under an existing scheme which provides for payment of a fixed amount after a certain period of time or where post-dated cheques have already been issued towards payment of income.

69. I also propose to provide for deduction of income-tax at source from interest on time deposits with banks at the rate of 20 per cent plus surcharge in the case of domestic companies and 10 per cent in the case of individuals and other non-corporate entities. The new provision will be applicable only to the deposits made on or after 1st July, 1995. No tax shall be deducted if the amount of interest credited or paid during a financial year is Rs. 10,000 or less branch-wise. Thus, persons having small deposits will not be affected by the requirement of deduction of tax. The existing facility of non-deduction of tax, where the recipient of interest has no taxable income will also be available. Interest on time deposits with primary co-operative credit societies, co-operative land mortgage banks and co-operative land development banks will be outside the scope of this provision.

70. Chapter XX C of the Income-tax Act empowers the Central Government to make pre-emptive purchase of immovable properties, beyond a prescribed limit, which, at present, is Rs. 10 lakhs. A single monetary limit for all the notified cities needs to be revised in the context of local variations in real estate prices. I, therefore, propose to make a provision for prescribing different monetary limits for different cities.

71. Hon'ble Members are aware that the searches conducted by the Income Tax Department are an important means of unearthing black money. However, undisclosed incomes have to be related to the different years in which the income was earned and as such assessments are unduly delayed. In order to make the procedure more effective, I am proposing a new scheme under which undisclosed income detected as a result of search shall be assessed separately at a flat rate of 60 per cent. An appeal against the order can be filed directly before the Income-tax Appellate Tribunal.

72. In allowing deduction for depreciation, 100 per cent deduction is allowed in the year of purchase for individual items of machinery or plant the value of which does not exceed Rs. 5,000. The written down value of such assets is thereafter taken as nil. This provision was introduced as difficulties were experienced in keeping record of items of small value for purposes of allowance of depreciation. After switching over to the concept of block of assets with effect from 1st April, 1988, all the items of plant and machinery falling in a block are pooled together for allowing depreciation at the prescribed rates. There is, therefore, no justification for the continuance of this provision. I, accordingly, propose to provide that even items of machinery of plant costing less than Rs. 5,000 will form part of a 'block of assets' and depreciation will be allowed on the same at the rate specified in the Income-tax Rules.

73. I propose to amend the provisions of the Income-tax Act to provide that the taxable income may be computed only on cash or mercantile basis. It is also being provided that the tax-payers shall follow accounting standards as may be notified by the Central Government from time to time for various businesses. This provision is being made applicable from accounting year starting from 1st April, 1996.

74. The calculation of capital gains on sale of bonus shares has led to several disputes. In order to simplify the position and avoid disputes, I propose that the cost of bonus shares for calculating the capital gains tax shall be taken at nil.

75. I now turn to my proposals regarding indirect taxes.

76. The thrust of my proposals is to continue the strategy of tax reform we have followed and reduce the cost of inputs to Indian producers, simplify the tax structure, minimize anomalies, promote competition and efficiency, lower prices paid by Indian consumers and thereby check the potential for inflation.

77. I shall deal first with import duties. The present peak rate of import duty of 65 per cent is still very high compared to other developing countries, let alone industrialised nations. I propose to continue the process of phased reduction in the peak rate by lowering it to 50 per cent.

78. The machinery and capital goods sector is a critical sector of our industry and it has responded extremely well to the new policies with a growth of 25 per cent in April—November, 1994. I propose a package of measures which will further rationalise and simplify the import duty structure as applicable to machinery and capital goods remove a number of anomalies and assist the industry in achieving a high rate of growth.

- * At present the general import duty rate on machinery items is 25 per cent but certain capital goods like generating sets and weighing machinery attract higher rate of duty. I am proposing to bring down the duty on these items also to 25 per cent.
- * The rate of import duty on machine tools, currently varies between 35 per cent and 45 per cent. I propose to unify the duty rates at 25 per cent which is the general rate for machinery. Parts of such machine tools will also generally attract duty of 25 per cent.
- * Components of capital goods generally attract an import duty of 25 per cent but components which contain electronic parts and components which are interchangeable with motor vehicle parts, attract higher rates. I propose to reduce the duty rate on these components to 25 per cent.
- * Quality control is a must for manufacturing industries if they have to improve the quality of their products. I am proposing to reduce the import duty on testing, quality control and other instruments from present rates varying from 40 per cent to 60 per cent to a uniform level of 25 per cent. Parts of such instruments in general will also attract the same rate.

79. These proposals will unify the customs duty rates for nearly 80 per cent of general machinery (both mechanical and electrical), machine tools, instruments and projects at 25 per cent. They will avoid anomalies relating to parts and components, reduce classification disputes and promote investment by reducing its cost.

80. Metals, ferrous and non-ferrous, are key inputs into capital goods and many other lines of production, many of which are undertaken by small scale producers. These items at present attract rates of duty varying from 50 per cent to 60 per cent. Ideally such materials should not attract rates of duty higher than those on the capital goods. But keeping in view the need to allow domestic producers of metals a reasonable transition period, I am proposing to reduce the import duty rates on ferrous and

non-ferrous metals to 40 per cent. For unwrought non-ferrous metals like copper, zini and lead, the import duty is proposed to be reduced to 35 per cent. Import duty on hot rolled coils of iron and steel for rerolling is proposed to be reduced from 40 per cent to 30 per cent, and that on stainless steel scrap from 30 per cent to 20 per cent. Import duty on spong iron is proposed to be reduced from 30 per cent to 20 per cent. I also propose to reduce the import duty on a number of non-metallic minerals from 65 per cent to 30 per cent.

81. I am also simplifying the import duty structure on ball or roller bearings which currently attract different rates of duty depending on size, weight and description. Henceforth all ball or roller bearings will attract a uniform duty of 25 per cent + Rs. 120/kg. The revised duty structure is likely to reduce the incentive for underinvoicing and smuggling.

82. Clothing and textiles are items of mass consumption. Yet our Import duties on raw materials and inputs used to manufacture synthetic yarns, fibres and fabrics are on the high side. In view of this, and keeping in mind the continuing inflationary pressure in this sensitive area, I propose to reduce import duty on xylenes from 30 per cent to 10 per cent to lower the cost of manufacturing DMT, PTA. I am also proposing to reduce the import duty on DMT, PTA and MEG, being essential raw materials for the manufacture of polyester fibre and polyester filament yarn, from 60 per cent to 35 per cent. On caprolactum, a basic raw material for nylon, the import duty is proposed to be reduced from 60 per cent to 45 per cent. These changes should substantially reduced input costs to the user industries. To help ensure that the benefits are reflected in the prices of the final products, I also propose to reduce the import duty on synthetic fibres and filament yarns to 45 per cent ad valorem.

83. I am also proposing to reduce the import duty on certain chemicals widely used in industry. On basic feedstocks like ethylene and benzene, the import duty is being reduced from 15 per cent to 10 per cent. On soda ash, caustic soda and linear alkyl benzene, the import duty is being reduced from 65 per cent to 40 per cent. On certain chemical intermediates like acrylonitrile, the import duty is being reduced from 30 per cent to 20 per cent. I am proposing to reduce the import duty on molasses from 65 per cent to 10 per cent to help the alcohol based chemical industries. The duty on LPG is also being reduced from 15 per cent to 10 per cent.

84. Electronics is a fast growing industry offering great promise for exports, employment and development in the small scale sector. In my last budget, I had conducted a major restructuring of duties to promote growth of this industry. As a further step in this direction, I propose to reduce the import duty on specified raw materials and piece parts from the present levels of 20 per cent and 30 per cent to a uniform level of 15 per cent on electronic components including printed circuit boards and colour monitor tubes from 40 per cent to 25 per cent, on populated printed circuit boards from 50 per cent and 65 per cent to 35 per cent and on computers, from 65 per cent to 40 per cent. I am also proposing to reduce the import duty on integrated circuits and hard disc drives to 25 per cent which is likely to reduce the grey market in these products. Import duty on picture tubes for colour TVs is being reduced from 65 per cent to 40 per cent. To give a boost to the telecom optical fibre cable industry, I propose to reduce the import duty on optical fibres from 40 per cent to 35 per cent. I am also proposing to reduce the import duty on both systems and application software to a uniform level of 10 per cent only. With these changes in duty structure, I expect this industry to show even more dynamism in future.

85. For promoting healthcare, last year I had simplified the import duty structure on medical equipment, exempted many types of life saving equipment from payment of duty, and abolished the certification procedure for availing of the exemption for charitable hospitals. In order to help manufacture and maintenance of medical equipment, I am extending the benefit of full exemption from import duty to all

parts of exempted life saving and sight saving equipment. Some crucial spare parts of other dutiable medical equipment such as populated PCB will attract an import duty of 15 per cent. I am also proposing to fully exempt linear accelerators, which are vital for the treatment of cancer patients. There are also proposals for reduction of import duty on a large number of drug intermediates from 50 per cent to 40 per cent.

86. Our printing industry needs quality paper so as to establish a foothold in the international field. With this in view, I am proposing to reduce the import duty on paper from 65 per cent to 40 per cent.

87. To promote exports of finished leather and make it more competitive, I propose to abolish the export duty on finished leather.

88. Agriculture is the lynch pin of our economic and employs two thirds of our labour force. In order to help agriculture and allied sectors directly, I propose reducing import duties on certain items. I am proposing to reduce the import duty on grand parent poultry stock from 30 per cent to 20 per cent. On certain drugs used as feed mix for poultry, the duty is being reduced from 65 per cent to 15 per cent. For the fishing industry, I propose to reduce the import duty on certain vaccines, prawn feed mix and preparations for prawn processing from 65 per cent to 15 per cent. Agriculture and allied sectors will also be helped by the general reduction in import duties on general machinery and components. I have, however, proposed an increase in import duty on malt and starch from 10 per cent to 30 per cent, that on silk cocoon from 30 per cent to 40 per cent and on oleopine resins from 10 per cent to 20 per cent in order to give necessary protection to these sectors.

89. I propose to raise the free baggage allowance for passengers coming to India from Rs. 4000 to Rs. 6000. Beyond this limit, the duty rate now is 100 per cent which I propose to reduce to 80 per cent. I hope this will provide welcome relief to our people working abroad and to travellers in general. At present import of goods through a courier attracts import duty at the rate of 100 per cent upto Rs. 10,000 and 200 per cent thereafter. There has been a long standing demand from industry that goods imported through a courier should be charged at the relevant rate for the item being imported. I am making a provision to this effect in the Finance Bill. Pending passage of the Legislation, I am proposing that goods imported by a courier will attract a duty of 80 per cent without any value limit.

90. I now turn to my proposals for excise duties.

91. In my earlier budgets, I had exempted from excise duty a large number of items of common consumption like processed food, dairy products, jam, jelly, butter, cheese, tea and coffee. Many other items of mass consumption like cooking oil, bicycles and their tyres, kerosene stoves, bread, spices and household utensils are also exempt from excise duty. My proposals in this budget will further reduce the burden of excise duties on articles which are widely consumed.

92. A number of articles of mass use are made of plastics. Plastics are also finding increasing use in agriculture and agro-processing. The present rate of duty on this basic material is 30 per cent. I propose to bring down the rate of duty on plastic to 25 per cent. On the dutiable articles made from plastics also, I propose to reduce the excise duty to 25 per cent. However, articles of plastics which are exempt at present will continue to be so. These measures are being combined with a reduction in the import duty on bulk plastics from rates varying between 45 per cent and 65 per cent to a uniform rate of 40 per cent.

93. At present, we have a uniform excise duty of 15 per cent on all metals except aluminium. I now propose to reduce the excise duty on aluminium also from 20 per cent to 15 per cent.

94. In order to remove areas of dispute in classification and to rationalise the duty structure, I propose a uniform excise duty of 15 per cent on parts of capital goods as against present rates which vary from 10 per cent to 25 per cent. This will avoid disputes as to whether a particular item should be considered as an article of metal or component of a machinery.

95. I am also proposing a concessional rate of excise duty of 10 per cent on glassware produced by the labour intensive mouth blown process as against the present rate of 20 per cent.

96. Many Honourable Members of Parliament have suggested that there are certain sectors of the industry which are both highly labour intensive and belong to the unorganised sector and that they deserve complete exemption from excise duty. Having regard to these requests, I propose to exempt the following from excise duty : —

- HDPE and polypropylene monofilaments which are mainly used for making fishing nets and mosquito nets;
- metal containers made without the aid of power;
- non-elastic narrow woven fabrics of cotton;
- unbranded surgical bandages; and
- tarpaulin cloth made without the aid of power.

97. As part of the process of reducing higher end duty rates, I am proposing to lower excise duty,—

- on aerated water from 50 per cent to 40 per cent;
- on air conditioning machinery from 60 per cent to 40 per cent;
- on cosmetics from 50 per cent to 40 per cent;
- on glazed tiles from 40 per cent to 30 per cent;
- on perfumed antiseptic cream from 30 per cent to 20 per cent.

98. I am also proposing reduction in excise duty in certain areas of general consumption,

- on polymer based paints from 30 per cent to 20 per cent;
- on cocoa and cocoa preparations from 25 per cent to 20 per cent;
- on malt based food preparations from 25 per cent to 20 per cent;
- on asbestos fibres from 20 per cent to 10 per cent;
- on asbestos cement articles from 30 per cent to 25 per cent;
- on audio and video magnetic tapes from 30 per cent to 20 per cent;
- on dry cell batteries from 25 per cent to 20 per cent;
- on coated fabrics from 35 per cent to 25 per cent;
- on ceramic laboratory ware from 30 per cent to 20 per cent;
- on fireworks from 20 per cent to 15 per cent;
- on parts of motor vehicles and two-wheelers from 20 per cent to 15 per cent;
- on glass containers from 30 per cent to 20 per cent.

99. I propose to reduce the excise duty on polyester filament yarn from 69 per cent to 57.5 per cent. The rate is still high but revenue constraints rule out any further reduction for the present. The concurrent reduction in import duties, indicated earlier, will help ensure that the benefit of excise duty reduction is passed on to consumers.

100. The textured polyester yarn industry has complained about the burden of excise duty of 69 per cent on the value addition in their industry. I am proposing suitable adjustment in the tariff value of textured yarn so as to reduce the total duty burden at the texturing stage from Rs. 10.35/kg to Rs. 4.60/kg. On sewing thread which currently attract excise duty at rates varying from 23 per cent to 69 per cent, I am proposing a uniform duty of 23 per cent.

101. I have some proposals which are in the nature of anti-evasion measures. I am proposing an excise duty of 10 per cent on wool tops so as to check evasion of excise duty at the woollen yarn stage. As full Modvat credit will be available, the tax will fall only on those who are evading excise duty at the yarn stage. I am also proposing a minimum excise duty of Rs. 10 per cent kilo on waste and scrap of fibre and yarn so as to discourage the tendency to clear good quality fibre and yarn in the guise of waste. It is also being clarified that yarn made predominantly from synthetic waste will attract the same rate of duty as yarn made from staple fibre.

102. Insulated wires and cables attract a duty of 30 per cent. As these have wide household and industrial application. I am proposing to reduce the duty to 25 per cent.

103. There is a persistent demand from the plastic woven bags manufacturers for extending Modvat to the users of such bags. I am now proposing that users of such plastic bags as well as jute bags be allowed full credit of excise duty paid on such bags. Cement industry is one of the major consumers of such bags. I am simultaneously proposing a modest increase in excise duty on cement from Rs. 330 to Rs. 350/MT for integrated cement plants and Rs. 185 to Rs. 200/MT for mini cement plants. For the mini cement plants using vertical shaft kilns, the daily clearance limit is also being raised from 200 to 300 MT per day.

104. Certain items of China and porcelain ware attract a duty of 30 per cent which is on the high side for a product which is increasingly of common use. With a view to giving relief to the consumers, I am proposing to reduce the duty to 15 per cent.

105. Small scale units play a significant role in the economy of the country. Currently, only units whose turnover of dutiable goods did not exceed Rs. 2 crore in the preceding financial year are eligible for the concessional rates of excise duty under the general small scale industry exemption scheme. I have received representations that the present limit of Rs. 2 crore is too low and that it acts as a disincentive to future growth. I am thus proposing to raise the eligibility limit for availing of the SSI exemption scheme to Rs. 3 crore.

106. There has been a perpetual problem with manufacturers of exempted goods as they may have to pay excise duty on waste and scrap generated during the process of manufacture. It does not seem very logical to bring these units under the excise control only for the purpose of charging duty on such waste and scrap. I am thus proposing to fully exempt waste and scrap which arise in the manufacture of exempted goods. This should help a large number of units in the small scale sector.

107. I am also proposing abolition of the system of filing of classification lists. From 1st May, 1995, the manufacturers need not file any classification list before clearing goods from the factory.

108. There have been requests from trade and industry for liberalisation and simplification of Modvat scheme. With this end in view, I am proposing the following relaxations in the Modvat Rules,—

- Allowing Modvat credit for specified quality control, testing, pollution control and R&D equipment;
- Utilisation of Modvat credit for payment of duty on any goods notified under the Modvat scheme;
- Allowing Modvat credit for furnace oil and low sulphur heavy stock used for generation of power in a factory manufacturing excisable goods.

109. I am also proposing to extend Modvat for tyre yarn used in tyres by imposing a duty of 20 per cent on the intermediate tyre cord fabrics. To make up for the revenue loss, the specific rates of duty on tyres are being raised by about 8 per cent. Excise duty on tyres for two wheeled and three wheeled vehicles is, however, not being raised.

110. I am proposing extension of Modvat scheme to industrial fabrics. In the case of woollen fabrics also, I am proposing to extend Modvat fully, as such fabrics already attract basic excise duty and enjoy limited Modvat facilities.

111. I am also proposing to broadly align the Central Excise Tariff on textiles on the lines of the harmonised system of nomenclature. This will help reduce classification disputes.

112. Consonant with the increase in prices, I am proposing an increase in the existing specific rates of duty on cigarettes by about 70 per cent.

113. I have also proposed certain amendments in the Finance Bill seeking to effect changes in the Customs Act, the Central Excises and Salt Act and excise and customs tariffs. These include certain consequential amendments to the customs tariff based on the amendments to the Harmonised Commodity Description and Coding System which has been adopted by our country in terms of International Convention on the Harmonised System. The amendments are merely enabling provisions and do not have significant revenue implications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them.

114. The increases in excise duties are expected to lead to a revenue gain of Rs. 335 crore while the reliefs will amount to Rs. 646 crore in a full year. Of the total net loss of Rs. 311 crore, the loss to the Centre will be Rs. 203 crore and that to the States Rs. 108 crore. On the customs side, the proposals would result in a revenue loss of Rs. 1179 crore. Applying conventional methods of estimation, the proposed changes in direct taxes are expected to lead to a revenue loss of about Rs. 900 crore on account of Income tax, of which the loss to the States would be about Rs. 700 crore. Total net loss to the Centre would thus be Rs. 1582 crore.

115. These methods do not take adequate account of the gains from simplification, rationalisation and improved tax compliance. Last year, the net loss from the revenue proposals on the basis of conventional estimates was placed at more than Rs. 4000 crore. However, I had predicted that because of gains from compliance and better administration our revenues would not suffer any loss. This optimism has been fully justified by performance as indicated in the Revised Estimates for 1994-95. The tax changes I have proposed in the budget are essentially a continuation of the efforts made in the previous year and I am confident that

the gains from the reform will ensure that there will be no revenue loss. I am not, therefore, assuming any revenue losses from my Budget proposals. Hence the fiscal deficit will remain at 5.5 per cent of GDP.

116. Copies of notifications giving effect to the changes in customs and excise duties will be laid on the Table of the House in due course.

117. Honourable members may recall that in my first Budget Speech, I had affirmed that no power on earth could stop an idea whose time had come. I had also stated that the emergency of India as a major economic power was such an idea. It is this vision, of a resurgent India, taking her rightful place as an economic power house in Asia, which has inspired our economic policies. Our Government has worked hard to convert this vision into a reality, and think the House will agree with me that our efforts have met with considerable success. We have sought to mobilise the collective will of our people for development through an action programme which commits us to the twin pursuit of excellence and social justice. There is no parallel example in the world of a country of India's size and diversity seeking to bring about a massive social and economic transformation in the framework of a democratic polity and an open society committed to the rule of law and individual freedom. India's experience is, therefore, of great worldwide significance. The world is certainly watching us with interest and expectation.

118. As I see it, India is on the threshold of unprecedented opportunities provided we have the wisdom to seize them. We have made a good beginning but there is still a vast unfinished agenda. We have to persevere in our efforts. This will call for hard work and dedication and a measure of self-discipline on the part of all sections of society. We must never forget that a higher standard of living for our people can become a reality only through an all round increase in productivity. Clearly there are no short cuts to it. We cannot simply spend our way into prosperity. Those of us in politics have a special responsibility. The pursuit of competitive politics must not be allowed to distract our people's attention from the basic task of nation building. Politics in this country must recapture the spirit of idealism and self sacrifice, which inspired our freedom struggle, and become a purposeful instrument of social change. This then is no time for rest or to fritter away our energies in partisan strife. It is a time for rededication and reaffirmation of our collective solemn resolve to work tirelessly for building a new India worthy of the dreams of the founding fathers of our Republic, an India which will enable our children and grand children to lead a life of dignity and self respect, to take pride in being Indian and to grapple effectively with the challenges of the twenty-first century.

119. Mr. Speaker, Sir with these words I commend this Budget to this august House.

N. P. BAGCHEE, Addl. Secy. (Budget)